

जैन मंदिर चोरी कांड का खुलासा, सात आरोपी गिरफ्तार, 13.15 लाख रुपये का मशरूका बरामद

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। थाना एरोड्रम पुलिस ने ग्रेटर बाबा परिसर स्थित श्री दिगम्बर जैन नवग्रह जिनालय में हुई चोरी की सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अष्ठधातु एवं चांदी की मूर्तियां, पूजा सामग्री और वारदात में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल सहित कुल 13 लाख 15 हजार रुपये मूल्य का मशरूका बरामद किया है।

पुलिस के अनुसार 4 मई 2026 को फरियादी अनुराग वैध ने थाना एरोड्रम में शिकायत दर्ज कराई थी कि 3 मई की रात अज्ञात बदमाश मंदिर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और अष्ठधातु की मूर्तियां, चांदी के बर्तन तथा अन्य धार्मिक सामग्री चोरी कर ले गए। शिकायत पर थाना एरोड्रम में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

देवास नाका पर वाल्व खराब होने से कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित, निगम ने शुरू किया सुधार कार्य

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। देवास नाका चौराहे पर स्थित ट्रेकमैन वाल्व के अचानक खराब हो जाने से शहर के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित हो गई है। सूचना मिलते ही नगर निगम आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण कर अधिकारियों को तत्काल सुधार कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।

स्थल निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त श्री आशीष पाठक सहित जलप्रदाय विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। आयुक्त ने वाल्व की खराबी को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश देते हुए नागरिकों को होने वाली असुविधा कम करने पर जोर दिया। वाल्व खराब होने के कारण स्कीम नंबर 114 पार्ट-1, स्कीम नंबर 78, राजीव आवास विहार, लोहा मंडी, स्कीम नंबर 113, स्कीम नंबर 136, स्कीम नंबर 78 स्लाइस-1 तथा स्कीम नंबर 78 स्लाइस-2 क्षेत्र की पानी की टंकियों से होने वाला जलप्रदाय अस्थायी रूप से प्रभावित रहेगा। नगर निगम के जलप्रदाय विभाग द्वारा सुधार कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है। प्रभाषित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त टैंकरों की व्यवस्था की गई है, ताकि नागरिकों को पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़े। नगर निगम ने बताया कि सोमवार रात आए आंधी-तूफान के कारण महेश्वर स्थित पंप स्टेशन में भी तकनीकी फॉल्ट आया था, जिससे कुछ टंकियां पूरी क्षमता से नहीं भर सकीं। हालांकि इन क्षेत्रों में सामान्य जलापूर्ति प्रभावित नहीं होने की संभावना है।

आउटर क्षेत्र के ढाबों पर इंदौर पुलिस की कार्रवाई, 14 ढाबों पर आवकारी एवट के तहत प्रकरण दर्ज

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर में अवैधानिक गतिविधियों पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से इंदौर पुलिस ने आउटर क्षेत्र के ढाबों पर विशेष जांच अभियान चलाया। थाना हीरानगर और थाना बाणगंगा पुलिस की संयुक्त टीम ने विभिन्न ढाबों पर आकस्मिक दबिश देकर शराबखोरी कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस आयुक्त श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री मयंक अवस्थी तथा पुलिस उपायुक्त जोन-3 श्री अभिषेक रंजन के मार्गदर्शन में यह अभियान संचालित किया गया। सहायक पुलिस आयुक्त हीरानगर श्रीमती रुबिना मिश्रवानी के नेतृत्व में थाना प्रभारी हीरानगर सुशील पटेल और थाना प्रभारी बाणगंगा सियाराम गुर्जर सहित पुलिस बल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने 1 जून की शाम से देर रात तक एमआर-10, सुपर कॉरिडोर और उज्जैन रोड क्षेत्र स्थित

कॉमन महिला मित्र को लेकर विवाद में छात्र पर चाकू से हमला, तीन आरोपी गिरफ्तार

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। थाना लसूडिया पुलिस ने रनेसा कॉलेज के छात्र पर चाकू से हमला कर हत्या का प्रयास करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कॉलेज में हुई मामूली कहासुनी और एक कॉमन महिला मित्र को लेकर हुए विवाद के चलते आरोपियों ने घटना को अंजाम



घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त जोन-1 नरेन्द्र सिंह रावत ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की थी। सहायक पुलिस आयुक्त विवेक सिंह चौहान के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने घटनास्थल से लेकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने संवेदनशीलता से सुनीं समस्याएं, मौके पर दिए समाधान के निर्देश

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी मंच बनकर उभरी है। जनसुनवाई में पहुंचे विभिन्न आवेदकों की समस्याओं को कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने संवेदनशीलता के साथ सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए त्वरित सहायता सुनिश्चित की। जनसुनवाई में पहुंचे श्री अमित रावत ने कलेक्टर श्री शिवम वर्मा को बताया कि उनके पास रहने के लिए स्वयं का आवास नहीं है तथा वे शासन की आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। कलेक्टर श्री वर्मा ने मामले को संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए संबंधित



पारिवारिक एवं आर्थिक परिस्थितियों से अवगत करवाया। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसी प्रकार जनसुनवाई में पहुंची श्रीमती ममता यादव की समस्या भी सुनी गई। उनकी स्थिति को देखते हुए कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने उन्हें भी आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में पहुंचे 84 प्रकरण, पुलिस कमिश्नर ने दिए त्वरित निराकरण के निर्देश

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। आमजन की शिकायतों के त्वरित निराकरण और प्रभावी समाधान के उद्देश्य से मंगलवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय द्वारा सुधार कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है। प्रभाषित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त टैंकरों की व्यवस्था की गई है, ताकि नागरिकों को पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़े। नगर निगम ने बताया कि सोमवार रात आए आंधी-तूफान के कारण महेश्वर स्थित पंप स्टेशन में भी तकनीकी फॉल्ट आया था, जिससे कुछ टंकियां पूरी क्षमता से नहीं भर सकीं। हालांकि इन क्षेत्रों में सामान्य जलापूर्ति प्रभावित नहीं होने की संभावना है।

मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार आयोजित इस जनसुनवाई में कुल 84 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें पारिवारिक विवाद, बेटा-बहू द्वारा प्रताड़ना, दामाद द्वारा बेटी से मिलने नहीं देने, भतीजों द्वारा परेशान करने, आपसी मतभेद, पैसों के लेन-देन से जुड़े मामले, प्लॉट, मकान और जमीन संबंधी धोखाधड़ी, वित्तीय उगी, सुनवाई न होने की

साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई। जांच के दौरान पुलिस ने पहले चरण में ललित चौहान, विशाल केवट, ओमप्रकाश चौहान और गीता बाई मकवाना को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से चांदी एवं अष्ठधातु की मूर्तियां, चांदी के कलश तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। बाद में आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।

पुलिस की लगातार कार्रवाई के दौरान 1 जून को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी में शामिल तीन अन्य आरोपी चांदी की वस्तुएं बेचने की फिराक में धार रोड से इंदौर आ रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों का पीछा किया। सुपर कॉरिडोर क्षेत्र में तेज बारिश और आंधी के दौरान मोटरसाइकिल फिसलने से आरोपी गिर पड़े, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें दबोच लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लखन मकवाना, दीपक और रामबाबू यादव के रूप में हुई। पूछताछ में उन्होंने जैन मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। इनके कब्जे से दो अष्ठधातु की मूर्तियां, एक अष्ठधातु की थाली, चांदी की मूर्तियां, पांडुशिला, कलश, कटोरा, चांदी की थालियां, चांदी के पाइप, वारदात में प्रयुक्त लोहे की टॉमी तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की गई।

पुलिस ने बताया कि सभी सात आरोपियों के खिलाफ मध्यप्रदेश सहित गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में चोरी, लूट एवं नकबजनी के कई मामले दर्ज हैं। मामले के खुलासे में थाना एरोड्रम, थाना तेजाजी नगर, साइबर सेल एवं फिंगर प्रिंट शाखा की टीमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है तथा उनके अपराधिक नेटवर्क और अन्य वारदातों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

परीक्षा कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता जरूरी: डॉ. ममता चन्द्रशेखर

इंदौर। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में मासिक विशेष व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत परीक्षा, परिणाम एवं प्रभाव विषय पर विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। महाविद्यालय की कलाम कक्षा में आयोजित कार्यक्रम में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ ने सहभागिता की।

कार्यक्रम की मुख्य वक्ता एवं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. ममता चन्द्रशेखर ने कहा कि उच्च शिक्षा में परीक्षा प्रणाली केवल वार्षिक अथवा सेमेस्टर परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सीसीई), प्रोजेक्ट कार्य, आसाइनमेंट, सेमिनार तथा अंतरिक मूल्यांकन भी विद्यार्थियों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्धता बनाए रखना प्रत्येक शिक्षक एवं कर्मचारी का दायित्व है।

डॉ. चन्द्रशेखर ने सीसीई, प्रोजेक्ट तथा

उत्कृष्ट कार्य के लिए 29 पुलिसकर्मी सम्मानित, प्रशस्ति पत्र व नगद पुरस्कार प्रदान

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड।

बेहतर पुलिसिंग को प्रोत्साहित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर

इंदौर में संचालित साप्ताहिक पुरस्कार कार्यक्रम के तहत मंगलवार को 29 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। पलासिया स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त श्री संतोष कुमार सिंह ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय एवं सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार प्रदान कर उनके कार्यों की सराहना की।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) श्री आर.के.



सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सम्मानित पुलिसकर्मियों को बधाई देते हुए उनके उत्कृष्ट कार्यों की प्रशंसा की और भविष्य में भी इसी तरह समर्पण एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

सम्मानित पुलिसकर्मियों में थाना एरोड्रम और तेजाजी नगर के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे, जिन्होंने जैन मंदिर चोरी प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी गया माल बरामद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थाना खजराना के

पुलिसकर्मियों को बकरीद पर्व के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभावी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सम्मानित किया गया। थाना एमजी रोड और छत्रीपुरा के पुलिसकर्मियों को विभिन्न अपराधों में

अज्ञात आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी तथा चोरी का माल बरामद करने में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। वहीं अपराध शाखा की टीम को संगठित गिरोह के फरार इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर सम्मान मिला। कार्यक्रम में अपराध शाखा की पुलिसकर्मी बबली खाकरे को हरियाणा में आयोजित योगासन प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक जीतने के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया।



आंतरिक मूल्यांकन संबंधी अंकों के समय पर संकलन, सत्यापन और पोर्टल पर प्रविष्टि की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि विद्यार्थियों के परिणामों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी सावधानी और

जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। उन्होंने परीक्षा परिणामों के संस्थागत प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किसी भी महाविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता उसके परीक्षा परिणामों, मूल्यांकन की विश्वसनीयता तथा अकादमिक अनुशासन से परिलक्षित होती है। उन्होंने सभी विभागों से परीक्षा एवं मूल्यांकन संबंधी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

व्याख्यान के दौरान परीक्षा प्रबंधन, मूल्यांकन प्रक्रिया, सीसीई एवं प्रोजेक्ट अंकों के संधारण तथा परिणामों की गुणवत्ता से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम ने उपस्थित शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ को परीक्षा संबंधी दायित्वों के प्रति अधिक सजग एवं उत्तरदायी बनने के लिए प्रेरित किया। अंत में डॉ. हरीश मिमरोट ने मुख्य वक्ता डॉ. ममता चन्द्रशेखर का आभार व्यक्त किया।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिवम वर्मा ने की बड़ी कार्रवाई

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा ने इंदौर जिले में गौ मांस का अवैध रूप से ऋय-विक्रय और परिवहन करने वाले दो कुख्यात आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने इन दोनों आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत निरुद्ध कर जेल भेजने के आदेश जारी किये हैं। इन दोनों आरोपियों के विरुद्ध अन्य गंभीर प्रकरण भी दर्ज हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा द्वारा जिन आरोपियों के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई की गई है, उनमें बण्डा बस्ती महु के कांदिर पिता फतेह मोहम्मद और मोहम्मद आबाद उर्फ कल्ल पिता मोहम्मद अनवर उर्फ अन्ना शामिल हैं। बताया गया कि इन दोनों आरोपियों के विरुद्ध गौ मांस का अवैध रूप से ऋय-विक्रय और परिवहन करने आदि के संबंध में अपराध पंजीबद्ध है। साथ ही इनके विरुद्ध धार्मिक और साम्प्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, लोकशांति भंग करने आदि प्रकरण दर्ज हैं।

मई 2026 में कृषि उपज मंडी समिति इन्दौर की आय में सुधार, प्राप्य राशि मिलने पर 17.97 प्रतिशत वृद्धि की संभावना

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कृषि उपज मंडी समिति इन्दौर द्वारा मई 2026 तक की आय (मंडी शुल्क) का विश्लेषण जारी किया गया है। विश्लेषण के अनुसार लगभग 13 माह बाद मंडी की वास्तविक मासिक आय में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही, गेहूँ उपार्जन पर प्राप्य मंडी शुल्क एवं आयार्जित तुअर पर दी गई छूट की प्रतिपूर्ति को शामिल करने पर मंडी समिति की आय में उल्लेखनीय वृद्धि परिलक्षित होती है।

मई माह में वास्तविक मंडी शुल्क आय में बढ़ोतरी- मंडी समिति के सचिव ने बताया कि मई 2025 में वास्तविक मंडी शुल्क प्राप्त 4 करोड़ 28 लाख 28 हजार 966 रुपये थी, जो मई 2026 में बढ़कर 4 करोड़ 31 लाख 44 हजार 367 रुपये हो गई है। इस प्रकार मई माह की आय में वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले लगभग 13 महीनों में पहली सकारात्मक वृद्धि मानी जा रही है। हालांकि अप्रैल-मई की संचयी अवधि में वर्ष 2025 के दौरान 10 करोड़ 26 लाख 95 हजार 630 रुपये की तुलना में वर्ष 2026 में 8 करोड़ 93 लाख 64 हजार 871 रुपये का वास्तविक मंडी शुल्क प्राप्त हुआ है। आयार्जित तुअर पर छूट एवं गेहूँ उपार्जन का प्रभाव- मंडी सचिव ने बताया कि वर्तमान आय दो प्रमुख कारणों से प्रभावित हुई है। चालू वित्तीय वर्ष अप्रैल-मई 2026 के दौरान आयार्जित तुअर (दलहन) पर कुल 1 करोड़ 56 लाख 86 हजार 902 रुपये की छूट दी गई है, जिसमें मई माह में 88 लाख 52 हजार 460 रुपये की छूट शामिल है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2026 में गेहूँ उपार्जन की कुल 6 लाख 13 हजार 448 किंटल मात्रा पर 2,625 रुपये प्रति किंटल के भाव से मंडी शुल्क की प्राप्य राशि 1 करोड़ 61 लाख 3 हजार 9 रुपये बनती है। इमें से मई माह का प्राप्य मंडी शुल्क 1 करोड़ 17 लाख 92 हजार 392 रुपये है। विश्लेषण में बताया गया है कि यदि शासन के प्रावधानों के अनुसार गेहूँ उपार्जन पर प्राप्य मंडी शुल्क प्राप्त हो जाता है तथा आयार्जित तुअर पर दी गई छूट की प्रतिपूर्ति को आय में शामिल किया जाता है, तो मंडी समिति की कुल संभावित आय 12 करोड़ 11 लाख 54 हजार 782 रुपये तक पहुंच जाएगी। इस स्थिति में वर्ष 2025 की समान अवधि की 10 करोड़ 26 लाख 95 हजार 630 रुपये की आय की तुलना में लगभग 17.97 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होगी। वहीं केवल मई माह के आधार पर संभावित वृद्धि का प्रतिशत 48.93 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।

शासकीय चरनोई भूमि से 35 दुकानों का अतिक्रमण हटाया गया

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशानुसार सोमवार को तहसील मल्हारगंज के ग्राम बांक में शासकीय चरनोई भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई सर्वे क्रमांक 182 एवं 187/1 की लगभग 1.500 हेक्टेयर भूमि पर की गई। कार्रवाई के दौरान तीन शेड से निर्मित गैरेज, ऑटो पार्इस तथा वाहन सविर्गम से संबंधित लगभग 35 दुकानों को हटाया गया। संबंधित भूमि को कलेक्टर इंदौर द्वारा धार रोड थाना, जनपद पंचायत इंदौर तथा फायर स्टेशन के लिए आवंटित किया गया है।

मंदसौर में बन रहा देश का सबसे बड़ा विद्युत सबस्टेशन, 14 हजार मेगावाट क्षमता

कलेक्टर गर्ग ने अरनिया जटिया में पम्प हाउस एवं रणायरा में पावर ग्रिड परियोजना का किया निरीक्षण

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर अदिती गर्ग ने मल्हारगढ़ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना अंतर्गत ग्राम अरनिया जटिया में निर्मित हो रहे पम्प हाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजना के नक्शे का भी अवलोकन किया तथा बैंक वाटर की संभावित समस्या के निराकरण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

जिला संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पम्प हाउस का निर्माण कार्य नवंबर माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान सीईओ जिला पंचायत अनुकूल जैन



सहित अन्य सभी संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। इसके पश्चात कलेक्टर श्रीमती गर्ग ने सजीत रोड स्थित ग्राम रणायरा में निर्माणाधीन पावर ग्रिड परियोजना का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने उन्हें परियोजना की प्रगति एवं तकनीकी विशेषताओं की जानकारी

दी। पावर ग्रिड में कलेक्टर ने पौधारोपण भी किया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा मंदसौर जिले के रणायरा ग्राम के समीप देश के सबसे बड़े विद्युत सबस्टेशनों में से एक का निर्माण किया जा रहा है। भारत सरकार के महारत्न

मुख्य उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केंद्रों से उत्पन्न विद्युत का प्रभावी एवं निबंध परेषण सुनिश्चित करना है। यह सबस्टेशन मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड से जुड़कर राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के वितरण एवं आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। परियोजना के पूर्ण होने पर मध्यप्रदेश देश के ऊर्जा मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित होगा। साथ ही यह परियोजना भारत सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति, कार्बन उत्सर्जन में कमी तथा ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगी। पावरग्रिड द्वारा अत्याधुनिक तकनीक एवं उच्च गुणवत्ता मानकों के साथ निर्माण कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। परियोजना के संचालन में आने के बाद प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों को इसका प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।



को मरीजों के उपयोग हेतु प्रारंभ नहीं किया गया और उसकी वर्तमान दुर्दशा समाप्त नहीं हुई, तो अखिल भारतीय पोरवाल युवा संगठन समाजजनों के साथ मिलकर व्यापक जनआंदोलन शुरू करेगा। युवा संगठन का कहना है कि यह केवल एक भवन का विषय नहीं, बल्कि समाज की आस्था, भाभाशाहों के सम्मान और जनसेवा की भावना का प्रश्न है। समाज की इस धरोहर को बचाने एवं पुनः जनहित में उपयोग सुनिश्चित करने के लिए संगठन हर स्तर पर संघर्ष करेगा। नारा - समाज की धरोहर का होगा सम्मान, पोरवाल वार्ड बनागा फिर से मरीजों की पहचान! उक्त जानकारी अखिल भारतीय पोरवाल युवा संगठन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राहुल वेद द्वारा दी गई।

वन विभाग में रिश्ततखोरी, अपने ही विभाग के कर्मचारी को भी नहीं छोड़ा, लोकायुक्त ने दबोचा



मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। वन विभाग में रिश्ततखोरी उजागर हो रही है। अपने ही विभाग के कर्मचारी को भी नहीं छोड़ा गया है। लोकायुक्त ने आरोपी को दबोचा लिया है। रिश्तत की रकम

तीन हजार है। सूत्रों के अनुसार मामले में दो और आरोपी बताए गए हैं, जिसके चलते कार्रवाई लम्बी घूमती रही है। इस संबंध में वन विभाग के मुखिया संजय रायखेड़े से संपर्क करने पर उनका मोबाइल नॉट रिस्पॉन्डिंग मिला। पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन आनन्द कुमार यादव के मार्गदर्शन में उज्जैन लोकायुक्त दल द्वारा कृष्ण प्रताप सिंह राठौर, स्थापना शाखा प्रभारी को रिश्तत लेते हुए मंदसौर में ट्रेन किया गया। जानकारी के अनुसार आवेदक ललित मीणा, वनरक्षक, गांधी सागर अभ्यारण पूर्व रेंज मंदसौर जिला मंदसौर द्वारा दिनांक 27 मई को लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थित होकर पुलिस अधीक्षक आनन्द कुमार यादव को शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर शिकायत की थी कि उसके द्वारा स्वयं के इलाज हेतु अहमदाबाद गुजरात जाने के लिए 43 दिवस के अर्जित अवकाश हेतु आवेदन लेकर कृष्णप्रताप सिंह राठौर, स्थापना शाखा प्रभारी सामान्य वन मंडल मंदसौर से मिला तो कृष्ण प्रताप सिंह राठौर द्वारा आईएफएमआईएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने और तीन चार हजार रुपए रिश्तत देने का कहा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत की तत्वीक की गई तो कृष्णप्रताप सिंह राठौर, स्थापना शाखा प्रभारी के द्वारा रिश्तत मांग की पुष्टि होने पर आज दिनांक 02 जून को ट्रेन आयोजित कर आरोपी कृष्ण प्रताप सिंह राठौर को आवेदक से 3,000 हजार रुपये रिश्तत लेते हुए सामान्य वन मंडल कार्यालय मंदसौर में स्थापना शाखा कक्ष में रंगे गंधों पकड़ा गया। लोकायुक्त दल में उप पुलिस अधीक्षक दिनेशचंद्र पटेल, निरीक्षक हिना डाबर, प्रचार हितेश ललवत, आरक्षक उमेश जाटव, आर मोहम्मद इसरार, आरक्षक श्याम शर्मा रहे।

औषधि विभाग द्वारा मेडिकल संस्थानों का निरीक्षण किया, दो मेडिकल फर्मों को कारण बताओ नोटीस जारी

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बताया गया कि बीपीएल चौराहा मन्दसौर में संचालित मेडिकल संस्थानों का निरीक्षण किया गया। जिसमे दवाईयों की एकसपायरी चेक की गई नशे के रूप में दुरुपयोग होने वाली दवाओं के स्टॉक, रिकॉर्ड्स चेक किये गए। निरीक्षण के दौरान सभी औषधि विक्रेताओं को स्टॉक रजिस्टर मेंटेन रखने हेतु निर्देशित किया गया। जिसमे श्रीजी मेडिकल बीपीएल चौराहा बस से दवाईयो के नमूने जांच हेतु लिए गए, सिटी मेडिकल, वीर फार्मा में शेरड्यूल एच। की औषधियों के क्रय विक्रय रिकॉर्ड्स दो दिवस में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा पूर्व में सीतामऊ तहसील में किए गए। निरीक्षण में अनियमितता पायी जाने पर दो फर्मों को पूजा मेडिकोज सीतामऊ, माँ आशपुरा मेडिकल सीतामऊ को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया नोटिस का जवाब प्राप्त होने के बाद आगामी कार्यवाही की जाएगी तथा सीतामऊ तहसील सभी औषधि विक्रेताओं के साथ बैठक लेकर नशे कि रूप में दुरुपयोग होने वाली औषधियों के रिकॉर्ड्स मेंटेनेड रखने तथा बिना डॉक्टर किए परामर्श पर दवा नहीं देने हेतु निर्देशित किया गया।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से दिल्ली में मिले राठौड़, पिपलिया स्टेशन पर ट्रेन ठहराव की मांग

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं युवा नेता सतीशसिंह राठौड़ ने नई दिल्ली में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भेंट कर क्षेत्र की महत्वपूर्ण रेल एवं यात्री सुविधाओं से जुड़ी मांगों को प्रमुखता से उठाया। इस दौरान उन्होंने रत्नलाम मंडल के पिपलिया रेलवे स्टेशन पर 9231/09232 उज्जैन, चित्तौड़गढ़-उज्जैन पैसंजर ट्रेन के नियमित ठहराव की मांग करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राठौड़ ने बताया कि पिपलिया नगर, रामपुरा, मनासा सहित आसपास के दर्जनों ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों नागरिक एवं श्रद्धालु प्रतिदिन विभिन्न कार्यों एवं धार्मिक यात्राओं के लिए उज्जैन आते-जाते हैं। विशेष रूप से भगवान महाकाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस रेलमार्ग का उपयोग करते हैं। वर्तमान में उक्त ट्रेन का पिपलिया रेलवे

स्टेशन पर ठहराव नहीं होने के कारण यात्रियों को मंदसौर अथवा नीमच जैसे बड़े स्टेशनों तक अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है, जिससे समय, धन और श्रम की अनावश्यक बर्बादी होती है। उन्होंने कहा कि पिपलिया रेलवे स्टेशन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, जहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री आवागमन करते हैं। इसके बावजूद कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव नहीं होने से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यदि उज्जैन-चित्तौड़गढ़ पैसंजर ट्रेन का ठहराव पिपलिया स्टेशन पर स्वीकृत किया जाता है तो न केवल स्थानीय नागरिकों बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी सीधा लाभ मिलेगा। इससे धार्मिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक एवं सामाजिक यात्राएं अधिक सुगम हो सकेंगी। राठौड़ ने ज्ञापन में पिपलिया रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के विस्तार की मांग भी उठाई। उन्होंने स्टेशन पर कोच गाइडेंस सिस्टम स्थापित करने,

यात्रियों के लिए बेहतर सूचना व्यवस्था विकसित करने तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं में वृद्धि की आवश्यकता बताई। उनका कहना था कि आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध होने से यात्रियों को ट्रेन के कोचों की सही जानकारी समय पर मिल सकेगी और यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ज्ञापन प्राप्त कर मांगों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। राठौड़ ने कहा कि क्षेत्र की जनता लंबे समय से इस मांग को उठा रही है और उन्हें विश्वास है कि केंद्र सरकार एवं रेल मंत्रालय जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगे। उन्होंने कहा कि पिपलिया स्टेशन पर ट्रेन ठहराव एवं यात्री सुविधाओं का विस्तार होने से क्षेत्र के हजारों लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा तथा यह क्षेत्र के विकास और बेहतर रेल संपर्क की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

संग्रहण स्थल पर क्लोरीन भी डाली गई। पीएचई के लेब इंचार्ज एच.एस. सोखल ने बताया कि पानी के नमूनों की जांच में जल गुणवत्ता सामान्य एवं सुरक्षित पाई गई है। उनका कहना है कि जहां पानी संग्रहित किया जा रहा है, वहां कोई समस्या नहीं मिली है। हालांकि पाइपलाइन में किसी प्रकार की खराबी या लीकेज

होने की संभावना सामने आई है, जिससे रास्ते में पानी दूषित हो सकता है। इधर गांव के अजय नागरिया का कहना है कि यदि जल स्रोत पर पानी पूरी तरह शुद्ध है तो फिर घरों तक पहुंचते-पहुंचते उसमें बदबू और गंदगी कैसे आ रही है? ग्रामीणों ने मांग की है कि केवल स्रोत से ही नहीं, बल्कि गांव के विभिन्न वाडों में नलों से निकल रहे पानी के नमूने लेकर भी जांच की जाए ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। ग्रामीणों का आरोप है कि नियमित रूप से नल कर वसूलने जाने के बावजूद उन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उनका कहना है कि समस्या का स्थायी समाधान किए बिना केवल जांच से लोगों की परेशानी दूर नहीं होगी। गांववासियों ने प्रशासन से पाइपलाइन की संपूर्ण तकनीकी जांच कर दोषपूर्ण हिस्सों को बदलने तथा नियमित जल परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। पीएचई के अधिकारी का कहना है यदि पाइपलाइन में किसी प्रकार की तकनीकी खामी पाई जाती है तो उसे प्रायः पंचायत के माध्यम से शीघ्र दूर किया जाएगा। वहीं ग्रामीण अब इस इंतजार में हैं कि जांच के बाद उन्हें वास्तव में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल कब तक उपलब्ध हो सकेगा।

सिंगोली हदसे पर कलेक्टर सख्त: छत गिरने से गई मां-बेटे की जान, पीड़ित परिवार को मिलेगी 9 लाख की सहायता; लापरवाह अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई



सिंगोली/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। सिंगोली में मकान की छत गिरने से मां-बेटे की दर्दनाक मौत के मामले में जिला प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सहायता राशि स्वीकृत करने का प्रकरण तैयार किया जा रहा है।

द वाॅचमैन पोस्ट से चर्चा में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा

ने बताया कि सिंगोली में छत गिरने की घटना सामने आई है। प्रशासन द्वारा मृतकों के परिजनों को सहायता के रूप में 4-4 लाख रुपये, अर्थात् कुल 8 लाख रुपये तथा क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत करने का प्रकरण तैयार किया जा रहा है। इस प्रकार पीड़ित परिवार को कुल 9 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने बताया कि हदसे में प्रभावित परिवार को अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पाया, इसकी भी जांच करवाई जाएगी। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या त्रुटि पाई जाती है तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि सिंगोली में हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। मां-बेटे की असामयिक मौत से नगर में शोक का माहौल बना हुआ है, वहीं प्रशासन की त्वरित पहल से पीड़ित परिवार को राहत मिलने की उम्मीद जगी है।

जनसुनवाई शिविर में एसपी राजेश त्यास सख्त, 15 सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का मौके पर निराकरण



नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और लंबित शिकायतों के निराकरण के उद्देश्य से मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम नीमच में जिला स्तरीय जनसुनवाई, शिकायत निवारण एवं सीएम हेल्पलाइन शिविर का आयोजन किया

गया। शिविर की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने की। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन जौन के निर्देश पर आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। जनसुनवाई के दौरान करीब 54 आवेदकों

ने अपनी समस्याएं पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखीं। एसपी राजेश व्यास ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संतोषित थाना प्रचारियों एवं अधिकारियों को शीघ्र और निष्पक्ष निराकरण के निर्देश दिए। शिविर के दौरान सीएम हेल्पलाइन की

लंबित शिकायतों पर भी विशेष फोकस किया गया। लेवल-1, लेवल-2 एवं लेवल-3 की कुल 15 शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण कर उन्हें बंद करवाया गया। इससे आवेदकों को राहत मिली और शिकायतों के समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल देखने को मिली।

एसपी राजेश व्यास ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन से प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने भूमि विवाद, पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों, सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य जनहित से संबंधित शिकायतों पर विशेष

संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। शिविर में एसडीओपी जावद रोहित राठौर, एसडीओपी मनासा निफिता सिंह, जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारी, शाखा प्रभारी तथा बड़ी संख्या में फरियादी उपस्थित रहे।

बड़े अस्पताल में पोरवाल वार्ड का उपयोग कबाड़ के रूप में जिसकी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं

7 दिन में सुधार नहीं हुआ तो पोरवाल युवा संगठन करेगा आंदोलन

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। अखिल भारतीय पोरवाल युवा संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल आज कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचा तथा जिला चिकित्सालय मंदसौर स्थित पोरवाल वार्ड की दुर्दशा एवं उपेक्षा को लेकर कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि समाज के भाभाशाहों एवं दानदाताओं द्वारा जनहित एवं मरीजों की सुविधा के लिए निर्मित पोरवाल वार्ड को अस्पताल प्रशासन द्वारा वर्षों से उपेक्षित रखा गया है। मरीजों के उपयोग में आने वाला यह वार्ड आज कबाड़ सामग्री का केंद्र बनकर रह गया है, जो समाज की भावनाओं एवं दानदाताओं के योगदान का खुला अपमान है।

प्रतिनिधिमंडल में समाज के वरिष्ठ रामगोपाल जी घाटिया(ऐरा

वाले) रामगोपाल जी गुप्ता (इंजीनियर), देवेन्द्र जी मरचया एडवोकेट,नरेंद्र उदिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पोरवाल युवा संगठन,संजय पोरवाल, संजय धनोतिया, अजय धनोतिया, निलेश पोरवाल एवं पंकज पोरवाल सहित समाज के अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे। एडीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 7 दिवस के भीतर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। युवा संगठन ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समयावधि में पोरवाल वार्ड

का कहना है कि यह केवल एक भवन का विषय नहीं, बल्कि समाज की आस्था, भाभाशाहों के सम्मान और जनसेवा की भावना का प्रश्न है। समाज की इस धरोहर को बचाने एवं पुनः जनहित में उपयोग सुनिश्चित करने के लिए संगठन हर स्तर पर संघर्ष करेगा। नारा - समाज की धरोहर का होगा सम्मान, पोरवाल वार्ड बनागा फिर से मरीजों की पहचान! उक्त जानकारी अखिल भारतीय पोरवाल युवा संगठन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राहुल वेद द्वारा दी गई।

सम्पादकीय डिजिटल क्रांति के बीच RBI का प्लास्टिक नोट लाने का फैसला

इस समाचार पत्र ने भी यह प्रकाशित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पॉलिमर बैंक नोट को फिर से शुरू करने जा रहा है। सरसरी तौर पर भले ही यह अनावश्यक लगे लेकिन यह निर्णय ध्यान देने लायक है। खासतौर पर तब जबकि भारत डिजिटल भुगतान में दुनिया में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। नकदी को अप्रासंगिक बनाने के बजाय भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति के साथ-साथ मुद्रा के उपयोग में लगातार वृद्धि हुई है।

इसलिए केंद्रीय बैंक के सामने चुनौती यह है कि मुद्रा के प्रवाह को अधिक कुशल, सुरक्षित और टिकाऊ बनाया जाए। रिजर्व बैंक की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट इस वास्तविकता को रेखांकित करती है। वर्ष 2025-26 में प्रचलित मुद्रा 1१ फीसदी से अधिक बढ़ी, जो पिछले वर्ष की 5.8 फीसदी वृद्धि से लगभग दोगुनी है, जबकि इसी दौरान डिजिटल भुगतान भी तेजी से विस्तार करता रहा।

दूसरे शब्दों में कहें तो डिजिटल और नकद भुगतान एक-दूसरे का स्थान नहीं ले रहे है बल्कि साथ-साथ मौजूद हैं। इस बढ़ते मुद्रा भंडार का प्रबंधन लगातार महंगा होता जा रहा है। वर्ष 2024-25 में बैंक नोट छापने पर 6,300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च हुई।

इसी समय लगातार 24 अग्रे धिसे-पिटे नोटों को प्रचलन से वापस लिया गया जो घिसी हुई मुद्रा को बदलने के परिचालन बोझ को उजागर करता है। छोटे मूल्य वर्ग के नोट जो बार-बार हाथ बदलते हैं वे खासतौर पर जल्दी खराब हो जाते हैं। ऐसे में यह उचित ही है कि रिजर्व बैंक 10 और 20 रुपये के नोटों के लिए एक प्रायोगिक परियोजना पर विचार कर रहा है। छोटे मूल्य वर्ग के नोटों का हिस्सा भी बढ़ाया जाना चाहिए।

यह कहना मुश्किल नहीं है कि छोटे मूल्य वर्ग के नोटों की उपलब्धता अक्सर लेनदेन को प्रभावित करती है। पॉलिमर नोट पतले प्लास्टिक से बने होते हैं जो ममी, गंदगी और फटने के मामले में अधिक सुरक्षित होते हैं। हालांकि पॉलिमर मुद्रा छापने की प्रारंभिक लागत अधिक होती है लेकिन अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताता है कि ये आर्थिक दृष्टि से बेहतर साबित होते हैं।

चूंकि पॉलिमर नोट्स काफी लंबे समय तक टिकते हैं इसलिए कम संख्या में नोटों को छापना, लाना ले जाना, संसाधित करना और नष्ट करना पड़ता है। सबसे अधिक बचत छोटे मूल्यवर्ग के नोटों में होती है जो सबसे अधिक प्रचलन में रहते हैं।

इस संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया का अनुभव उल्लेखनीय है। पॉलिमर मुद्रा के मामले में अगुआ होने के नाते उसने अनुमान लगाया कि इस बदलाव से प्रतिस्थापन और हैंडलिंग लागत में कमी के कारण दीर्घकालिक बचत हुई। ऑस्ट्रेलिया के कागजी नोट पहले छोटे मूल्यवर्ग में केवल 6 से १2 महीने तक चलते थे, जबकि पॉलिमर नोट कई वर्षों तक टिके। कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देशों ने भी पॉलिमर नोट अपनाए हैं जिनका कारण टिकाऊपन, उन्नत सुरक्षा और कम जीवनचक्र लागत है।

पारदर्शी विंडो और माइक्रो-ऑप्टिक तत्व जैसी उन्नत सुरक्षा विशेषताएं पॉलिमर नोटों को नकल के लिहाज से भी अधिक सुरक्षित बनाती हैं। पर्यावरणीय तर्क भी उतना ही प्रभावशाली है। विदेश में केंद्रीय बैंकों द्वारा किए गए अध्ययनों में पाया गया है कि पॉलिमर नोट अपने जीवनकाल में कम संसाधनों का उपभोग करते हैं। इसके अलावा चलन से हटाए गए पॉलिमर नोटों को अन्य प्लास्टिक उत्पादों में पुनर्चक्रित भी किया जा सकता है। ये सभी लाभ विचारणीय हैं।

इस प्रकार अग्रिम लागत, एटीएम के अनुकूल बनाए जाने, नकदी-प्रबंधन अधोसंरचना और जनस्वीकृति का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना होगा। भारत का 2०12 में पॉलिमर नोट पेश करने का पहले का प्रयास तकनीकी सीमाओं के कारण असफल रहा था। विशेष रूप से पुराने एटीएम और गिनती मशीनों की अक्षमता के कारण ऐसा हुआ जो प्लास्टिक की सामग्री को सही ढंग से पहचानने, संभालने और वितरित करने में सक्षम नहीं थीं। पॉलिमर नोट उपयोगकर्ताओं को धिसे-पिटे और फटे नोटों से नियमित रूप से निपटने की बड़ी असुविधा से भी राहत देंगे। खासकर छोटे मूल्यवर्ग के नोटों में क्योंकि उन्हें बदलवाना हमेशा आसान नहीं होता।

स्त्री की शक्तियों को नया आयाम देता है सहजयोग



जागृत स्त्री ही सुखी परिवार और श्रेष्ठ समाज का आधार है।

स्त्री सुष्टि की आधारशिला है। वह केवल परिवार की धुरी ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण की भी महत्वपूर्ण शक्ति है। आज की व्यस्त जीवनशैली में महिलाओं को अनेक भूमिकाएँ निभानी पड़ती हैं, जिसके कारण

मानसिक तनाव, भावनात्मक दबाव और असंतुलन जैसी चुनौतियाँ सामने आती हैं। ऐसे समय में ध्यान स्त्री शक्ति के लिए एक अमूल्य साधन सिद्ध होता है, और सहजयोग इस दिशा में एक सरल एवं प्रभावशाली मार्ग प्रदान करता है।

सहजयोग एक आत्म-साक्षात्कार आधारित ध्यान पद्धति है, जिसकी स्थापना श्री माताजी निर्मला देवी जी ने की। सहज का अर्थ है स्वाभाविक और योग का अर्थ है मिलन। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक शक्ति, अर्थात् कुंडलिनी के, जागरण द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है। सहजयोग के ध्यान मन को शांत करता है, विचारों की अंधकारिता को कम करता है तथा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाता है। इससे महिलाओं में धैर्य, संतुलन और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है।

सहजयोग के अनुसार प्रत्येक महिला के भीतर मातृत्व, प्रेम, करुणा और संरक्षण की दिव्य शक्तियाँ विद्यमान हैं। ध्यान के माध्यम से ये गुण और अधिक प्रकट होते हैं, जिससे वह न केवल स्वयं को सशक्त बनाती है बल्कि अपने परिवार और समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। जब एक महिला अपने भीतर की शांति और शक्ति से जुड़ जाती है, तब वह जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक सहजता और आत्मबल के साथ कर पाती है।

श्री माताजी ने स्त्री धर्म का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत करते हुए अपने जीवन में एक आदर्श पुरी, पत्नी, माता और विश्वमाता की भूमिका का निर्वहन किया। उन्होंने परिवार की सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण समर्पण के साथ निभते हुए मानवता के आध्यात्मिक उद्धान का महान कार्य किया। गृहस्थ जीवन में रहते हुए उन्होंने यह सिद्ध किया कि आध्यात्मिकता और पारिवारिक कर्तव्य एक-दूसरे के पूरक हैं। मातृत्व, करुणा, प्रेम, क्षमा और त्याग जैसे स्त्री-सुलभ गुणों को उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ किया तथा सहजयोग के माध्यम से लाखों लोगों को आत्मसाक्षात्कार प्रदान कर विश्व में शांति, एकता और धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। श्री माताजी का जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि एक जागृत और संतुलित नारी पूरे समाज के उत्थान की प्रेरक शक्ति बन सकती है।

सहजयोग महिलाओं को उनकी अंतर्निहित शक्तियों का अनुभव कराकर उन्हें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है। एक सशक्त और संतुलित महिला ही एक सशक्त परिवार, समाज और राष्ट्र की आधारशिला होती है।

पेपर लीक की आड़ में डिजिटल शिक्षा पर अंजना का ‘दो कौड़ी’ तंज

भारतीय शिक्षा जगत में यह शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो कि एक टीवी स्टूडियो में कहीं गई टिप्पणी इतनी तेजी से राष्ट्रीय बहस का विषय बन जाए। लेकिन जब वरिष्ठ एंकर अंजना ओम कश्यप ने नीट पेपर लीक पर चर्चा के दौरान यूट्यूब शिक्षकों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ‘एक्सप्लेनर बनाते हैं, जानते कुछ नहीं’- और उन्हें ‘दो कौड़ी के यूट्यूब गुरु’ तक कह दिया, तो यह सिर्फ एक टीवी बहस नहीं रही। यह बयान देखते ही देखते ‘ब्लैकबोर्ड पर ब्रेकिंग न्यूज़’ बन गया। वास्तव में, यह डिजिटल शिक्षा की बढ़ती ताकत के सामने मुख्यधारा मीडिया की असहजता को उजागर करता है। अंजना का यह हमला तथ्यों से अधिक पूर्वाग्रह का प्रतीक प्रतीत होता है।

जब लाखों छात्रों का भरोसा किसी मंच से जुड़ जाए, तो उस पर उठी उंगली केवल व्यक्तियों पर नहीं, पूरी व्यवस्था पर सवाल बन जाती है। अंजना ओम कश्यप की इस टिप्पणी को खान सर, अभिनय शर्मा जैसे लोकप्रिय यूट्यूब शिक्षकों पर भी लागू माना गया। उन्होंने कुछ डिजिटल शिक्षकों को ‘बड़ा फ़ॉड’ तक कह दिया। यह टिप्पणी ऐसे समय आई, जब लाखों छात्र ऑनलाइन शिक्षा के सहारे अपने सपने संचार रहे हैं। इसलिए इसे केवल कुछ शिक्षकों पर नहीं, बल्कि पूरे डिजिटल शिक्षा जगत को साख़ पर नज़र माना गया। सवाल है, क्या यह आलोचना तथ्यों पर आधारित है या महज सुविध्याँ बटोरने की कोशिश? क्या कुछ अपवादों के आधार पर पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा करना उचित है?

अमेरिका-चीन की नजदीकी भारत के लिए बड़ा इम्तिहान

अमेरिकी विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो की 23 से 26 मई तक की भारत यात्रा में ताजमहल की यात्रा के अलावा दो ख़ास बातें थीं। पहली बात द्विपक्षीय थी यानी भारतीय विदेश मंत्री एस जयरंकर के साथ बातचीत जबकि दूसरा अवसर था क़ा़ड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में शिरकत करना। यह राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में तीसरी ऐसी बैठक थी। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोना और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी क़ा़ड बैठक से इतर रूबियो के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। ये द्विपक्षीय बैठकें भी बहुपक्षीय बैठकों की तरह ही महत्वपूर्ण रहें। इन बैठकों का क़ा़ड की बैठक से अलग भी विश्लेषण किया जाना चाहिए।

रूबियो की यात्रा का उद्देश्य साफ़ तौर पर भारत के साथ रिश्तों में सुधार करना था। बीते एक साल में दोनों देशों के रिश्तों में काफी गिरावट आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल ख़रीदने के लिए दंडात्मक शुल्क लगाए जबकि उन्होंने चीन, तुर्किये और हंगरी जैसे ऐसा ही करने वाले अन्य देशों को रियायत दी। इसके अलावा वह अक्सर भारत के बारे में अशोभनीय भाषा बोलते हैं। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था तक कहा।

उनकी प्रशासनिक टीम के कई अधिकारियों ने भारत के लिए और भी अधिक अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है और यह ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (मागा) समर्थक समूह के भीतर भी गुंजता रहा है। भारत को ट्रंप के आव्रजन विरोधी अभियान का भी खामियाजा भुगतना पड़ा है, जिसमें एच१-बी वीजा पर प्रतिबंध शामिल है जो वर्षों से पेशेवर भारतीयों के लिए करियर में आगे बढ़ने का माध्यम रहे हैं।

पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व के साथ अमेरिका की बढ़ती नजदीकी और ईरान के साथ चल रहे युद्ध में मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान को दी गई प्रमुखता ने भारत-पाकिस्तान को एक तानात्र पर रखने की आशंका को फिर से जीवित कर दिया है और इस चिंता को जन्म दिया है कि पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका और चीन दोनों से समर्थन प्राप्त कर सकता है भले ही इन दोनों संरक्षकों के बीच तीव्र टकराव के दिन क्यों न हों। और भी महत्त्वपूर्ण यह संभावना रही है कि अमेरिका और चीन के बीच कुछ हद तक रणनीतिक समायोजन हो सकता है, जिसे ट्रंप की हालिया चीन यात्रा ने और मजबूत किया है। दोनों पक्षों ने रचनात्मक रूप से रणनीतिक टिकाऊपन को आगे बढ़ाने और आर्थिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस सहित कई विवादोत्पद मुद्दों पर संवाद में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की। व्यापार-संबंधी मुद्दों को संभालने के लिए एक व्यापार बोर्ड और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक निवेश बोर्ड के अलावा, स्पष्ट रूप से परिभाषित मानकों के भीतर, यह दर्शाती है कि चीन से दूरी बनाने के बजाय उससे जुड़े जोखिम कम करना अब अमेरिका की पसंदीदा रणनीति है।

-सुनील कुमार महला

शोर और आरोपों से परे, किसी भी व्यवस्था का

मूल्यांकन उसके परिणामों से होता है। पिछले एक दशक में यूट्यूब आधारित शिक्षा ने लाखों छात्रों तक ज्ञान पहुंचाया, जिनकी पहुंच महंगी कौचिंग तक नहीं थी। खान सर और अभिनय शर्मा जैसे शिक्षकों ने दूर-दराज क्षेत्रों के युवाओं को अवसर, मार्गदर्शन और आत्मविश्वास दिया। इनके पक्ष में सबसे बड़ा प्रमाण लाखों सफल छात्र हैं। यदि ये ‘कुछ नहीं जानते’, तो यह सफलता कैसे संभव हुई? हालाँकि कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन उनसे पूरे योगदान को नकारा नहीं जा सकता। अंजना जी, यह आरोप केवल शिक्षकों पर नहीं, उनके समर्पण और मेहनत पर भी सवाल उठता है।

जब दुनिया थम-सी गई थी और शिक्षा के पारंपरिक रास्ते बंद हो गए थे, तब डिजिटल मंचों ने सीखने की लौ बुझने नहीं दी। कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षक लाखों विद्यार्थियों के लिए सहारा बने। स्कूलों और कक्षाओं के बंद रहने पर मोबाइल और इंटरनेट के जरिए शिक्षा घर-घर पहुंची। जहाँ कई कौचिंग संस्थानों की फीस लाखों रुपये तक है, वहीं अनेक यूट्यूब शिक्षक मुफ्त या कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते रहे। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने शिक्षा को सीमित दायरों से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाया है। ऐसे योगदान को अनदेखा कर पूरे समुदाय को फ़ॉड बताना न केवल अनुचित, बल्कि एकतरफ़ा दृष्टिकोण भी है। हालाँकि कुछ चैनलों में क्लिकबेट, भ्रामक थंबनेल और पेड कोर्स की आक्रामक मार्केटिंग जैसी समस्याएँ भी मौजूद हैं।

स्वस्थ जीवन एवं स्वस्थ पर्यावरण का आधार है साइकिल

हर वर्ष 3 जून को मनाया जाने वाला विश्व साइकिल दिवस केवल एक साधारण वाहन के सम्मान का अवसर नहीं है, बल्कि यह मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता और सतत विकास के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, बढ़ती बीमारियों और यातायात संकट जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब साइकिल एक ऐसे सरल समाधान के रूप में उभरती है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र-तीनों के लिए समान रूप से लाभकारी है। विश्व साइकिल दिवस 2026 को थैम ‘हरियाली भरे भविष्य के लिए साइकिल चलाना’ अत्यंत सार्थक और समानुक्तूल है। यह थीम हमें याद दिलाती है कि यदि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित पृथ्वी छोड़नी है, तो हमें अपने परिवहन के तौर-तरीकों में बदलाव लाना होगा और साइकिल को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा।

साइकिल मानव सभ्यता के उन आविष्कारों में से एक है जिसने दो शताब्दियों से अधिक समय तक अपनी उपयोगिता बनाए रखी है। तकनीकी क्रांति के इस युग में भी इसकी प्रासंगिकता कम नहीं हुई है, बल्कि नई चुनौतियों के बीच इसका महत्व और बढ़ गया है। यह एक ऐसा वाहन है जो बिना पेट्रोल, डीजल या बिजली के चलता है, न कोई धुआँ छोड़ता है और न ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2018 में इसे वैश्विक स्तर पर मान्यता देते हुए विश्व साइकिल दिवस घोषित किया। आधुनिक जीवनशैली ने मनुष्य को सुविधाएँ तो बहुत दी हैं, लेकिन इसके साथ अनेक स्वास्थ्य समस्याएँ भी पैदा कर दी हैं। घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करना, शारीरिक श्रम का अभाव, वाहन-निर्भरता और तनावपूर्ण जीवन ने मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग तथा मानसिक अवसाद जैसी समस्याओं को बढ़ा दिया है। ऐसे समय में साइकिल केवल एक परिवहन साधन नहीं, बल्कि एक प्रभावी स्वास्थ्य-सहचर बनकर सामने आती है।

चिकित्सकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार नियमित साइकिल चलाना एक उत्कृष्ट कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम है। इससे हृदय मजबूत होता है, रक्त संचार बेहतर होता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और शरीर की अतिरिक्त कैलोरी खर्च होती है। साइकिल चलाने से मांसपेशियाँ सुदृढ़ होती हैं तथा जोड़ों पर अत्यधिक दबाव भी नहीं पड़ता, इसलिए यह सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए उत्पुष्ट व्यायाम माना जाता है। विशेष रूप से

ब्याज दर बढ़ाना नहीं है समाधान

नीतिगत द्रें तय करने वाली भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की संस्था मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की इस सप्ताह (3 से 5 जून) बैठक होने वाली है। चालू वित्त वर्ष में एमपीसी की यह दूसरी बैठक होगी। बड़ा सवाल यह है कि इस बैठक से क्या निकल कर आने वाला है?

अप्रैल में 5 से 8 तारीख तक एमपीसी की पहली बैठक के बाद पिछले दो महीनों में दुनिया के कई केंद्रीय बैंकों ने प्रमुख नीतिगत दरों में बढ़ोतरी की है। उस समय पश्चिम एशिया संकट को पांच सप्ताह ही हुए थे। दूसरी बैठक भी इसी संकट की छाया में हो रही है।

क्या आरबीआई दुनिया के दूसरे केंद्रीय बैंकों की तर्ज पर नीतिगत दर बढ़ाएगा या अमेरिकी फेडरल रिजर्व, यूरोपीय केंद्रीय बैंक, बैंक ऑफ़ इंग्लैंड और बैंक ऑफ़ कनाडा की तरह दरें अपरिवर्तित रखेगा? ये चारो केंद्रीय बैंक दर बढ़ोतरी को लेकर गहन मंथन कर रहे हैं। इन्होंने आखिरी बार जुलाई और सितंबर 2023 के बीच अपनी नीतिगत दरें बढ़ाई थीं।

एमपीसी की पिछली बैठक में रीपो दर 5.25 फीसदी पर अपरिवर्तित रखी गई थी। स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5 फीसदी और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर 5.5फीसदी पर अपरिवर्तित रही। अप्रैल में एमपीसी की बैठक के दौरान 364 दिन के ट्रेजरी बिल पर यील्ड 5.63 फीसदी, तीन महीने की अवधि के बिल पर यील्ड 5.3 फीसदी और 182 दिनों की अवधि के बिल पर यील्ड 5.53 फीसदी थी। एक वर्षीय सर्टिफिकेट ऑफ़ डिपॉजिट (सीडी) की दर 7.1 से 7.4 फीसदी और एक वर्षीय कम/रीजियल पेपर (सीपी) पर ब्याज दर 7.4 से 7.6 फीसदी के बीच थी।

मगर तब से 364 दिनों के ट्रेजरी बिल पर यील्ड बढ़कर 6.02 फीसदी, तीन महीने के बिल पर 5.56 फीसदी और 182 दिनों की अवधि के बिल पर 5.735 फीसदी हो गई है। एक वर्षीय सीडी पर दर अब 7.75 से 8.25 फीसदी और एक वर्ष के सीपी पर दर 7.6 से 8फीसदी के बीच है।

तो क्या मौजूदा हालात में आरबीआई को रीपो दर बढ़ानी चाहिए? आइए, पहले कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण संकेतकों पर नजर डालें। 10 वर्ष की अवधि पर बॉन्ड यील्ड 6.90 फीसदी और 7.14 फीसदी के बीच रही है। इस दौरान अमेरिका के 10 वर्ष की अवधि के बॉन्ड और भारत के 10 वर्ष के बॉन्ड पर यील्ड के बीच अंतर 2.61 फीसदी अंक से घटकर 2.52 फीसदी अंक हो गया है। यह कमी इस क्षेत्र में विदेशी मुद्रा प्रवाह के लिए एक समस्या बन गई है।

विवाद के बीच शिक्षकों की प्रतिक्रिया ने अंजना के आरोपों पर नए सवाल खड़े कर दिए। अभिनय सर और खान सर जैसे शिक्षकों ने कहा कि उनका काम छात्रों का भविष्य संवराना है, न कि सनसनी फैलाना। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई उन्हें ज्ञानहीन सिद्ध कर दे, तो वे सीखने को तैयार हैं, लेकिन निराधार आरोप स्वीकार्य नहीं हैं। दूसरी ओर, सोशल मीडिया पर छात्रों ने भी खुलकर उनका समर्थन किया। हजारों प्रतिक्रियाओं में छात्रों ने बताया कि इन शिक्षकों ने शिक्षा को महंगे दायरों से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाया है। ऐसे में ‘दो कौड़ी’ जैसी टिप्पणी केवल शिक्षकों पर नहीं, बल्कि उन लाखों छात्रों और परिवारों के विश्वास पर भी चोट करती है, जो उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते हैं।

इस प्रकरण ने मुख्यधारा मीडिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए हैं। जब यूट्यूब शिक्षक नीट लीक, सीबीएसई विवादों और शिक्षा व्यवस्था की खामियों पर आवाज उठाते हैं, तो उन्हें फ़ॉड कहकर खारिज कर दिया जाता है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या टीवी एंकर हर विषय के अंतिम विशेषज्ञ हैं? यदि डिजिटल मंचों की विश्वसनीयता पर संदेह किया जाता है, तो टीआरपी-केंद्रित बहसों की निष्पक्षता भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। अंजना ओम कश्यप का बयान इसी विरोधाभास को उजागर करता है। एक ओर डिजिटल शिक्षक शिक्षा की पहुंच बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके योगदान पर संदेह जताया जा रहा है।

डिजिटल शिक्षा जगत भी कमियों से पूरी तरह अछूता

नहीं है। कुछ यूट्यूब चैनलों पर क्लिकबेट और भ्रामक जानकारी की समस्या मौजूद है, जिसकी आलोचना और जवाबदेही आवश्यक है। कुछ टीचर्स पर पेपर लीक या गलत मार्गदर्शन के आरोप भी लगते रहे हैं। लेकिन कुछ उदाहरणों के आधार पर पूरे समुदाय को ‘फ़ॉड’ या ‘दो कौड़ी का’ कहना उचित नहीं। शिक्षा में गुणवत्ता जरूरी है, पर उसके नाम पर पूरे आंदोलन को अपमानित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यवस्था का मूल्यांकन तथ्यों और परिणामों से होना चाहिए, न कि अपमानजनक टिप्पणियों से। अंजना का बयान इसी अतिसामान्यीकरण की मिसाल प्रतीत होता है।

वस्तुतः, इस पूरे विवाद का केंद्र कोई एंकर या शिक्षक नहीं है, बल्कि शिक्षा का बदलात परिदृश्य है। आज करोड़ों छात्र सीमित संसाधनों के बीच डिजिटल मंचों के सहारे अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यधारा मीडिया और डिजिटल शिक्षा जगत, दोनों से संतुलन, जवाबदेही और संवाद की अपेक्षा है। किसी शिक्षक का मूल्यांकन आरोपों या उपहास से नहीं, बल्कि उसके विद्यार्थियों की उपलब्धियों से होना चाहिए। ‘दो कौड़ी के गुरु’ जैसी टिप्पणी केवल शिक्षकों पर नहीं, बल्कि उन करोड़ों छात्रों के विश्वास और आकांक्षाओं पर भी आधारित है; ऐसे में संबोधित टिप्पणी पर पुनर्विचार और खेद की अपेक्षा स्वाभाविक है। शिक्षा राष्ट्र की नींव है, इसलिए इस पर विमर्श पूर्वाग्रह नहीं, तथ्यों और सम्मान के आधार पर होना चाहिए।

-प्रो. आरके जैन

मानते हैं, जबकि विकसित देशों में साइकिल प्रतिष्ठ, स्वास्थ्य

चेतना और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का प्रतीक बन चुकी है। नीदरलैंड, डेन्मार्क और जर्मनी जैसे देशों ने साइकिल को शहरी जीवन का केंद्र बनाया है। वहाँ अलग साइकिल लेन, सुरक्षित मार्ग और अनुकूल नीतियाँ उपलब्ध हैं। भारत को भी इस दिशा में गंभीर पहल करनी होगी।

समय की भाँप है कि साइकिल को केवल खेल या मनोरंजन का साधन न मानकर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग बनाया जाए। शहरों में सुरक्षित साइकिल ट्रैक, सार्वजनिक साइकिल शेयरिंग सिस्टम, कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में साइकिल उपयोग को प्रोत्साहन तथा सरकारी स्तर पर प्रोत्साहन योजनाएँ विकसित की जानी चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में साइकिल चलाने की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। तथा लोगों को इसके स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय लाभों के प्रति जागरूक किया जाए। विश्व साइकिल दिवस मनाने का उद्देश्य भी यही है कि समाज साइकिल के बहुआयामी महत्व को समझे और इसे दैनिक जीवन में अपनाए। यह दिवस हमें बताता है कि बड़े परिवर्तन हमेशा जटिल तकनीकों से नहीं आतेय कभी-कभी एक साधारण दो पहियों वाला वाहन भी मानवता को बेहतर भविष्य की दिशा दिखा सकता है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम साइकिल को अतीत की वस्तु नहीं, बल्कि भविष्य की आवश्यकता के रूप में देखें। जब दुनिया सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है, तब साइकिल एक ऐसा माध्यम है जो स्वास्थ्य, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय-सभी क्षेत्रों में सकारात्मक योगदान दे सकती है। विश्व साइकिल दिवस हमें यह संदेश देता है कि यदि हम स्वस्थ शरीर, स्वच्छ वातावरण और संतुलित जीवन चाहते हैं, तो साइकिल को पुनः अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। यह केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि एक जीवन-दर्शन है-सादगी, संतुलन, स्वास्थ्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य का जीवन-दर्शन। आने वाला भारत तभी अधिक स्वस्थ, हरित और प्रतिशील बन सकेगा जब साइकिल फिर से उसकी सड़कों, गलियों और जनजीवन की धड़कन बनेगी। यही विश्व साइकिल दिवस की सार्थकता है और यही हरियाली भरे भविष्य की दिशा में हमारा सामूहिक संकल्प होना चाहिए।

-ललित गर्ग

क्या आरबीआई आपूर्ति में अचानक आए व्यवधान और इस दशक के सबसे कमजोर मौनसून की आशंका के कारण मुद्रास्फीति से निपटने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि करेगा? मेरा अनुमान है कि आरबीआई ऐसा करने से परहेज करेगा। वह सभी आंकड़ों पर नजर रखना जारी रखेगा और ब्याज दर में बदलाव करने से पहले इंतजार करेगा। चूंकि, वर्तमान रुख तटस्थ है इसलिए उसके पास कुछ न कुछ गुंजाइश तो जरूर है।

इस समय चार प्रमुख चिंताएं हैं जिनमें रुपया कमजोर होना, विदेशी पूंजी की निकासी, आपूर्ति व्यवस्था में बाधा आने से ऊंची मुद्रास्फीति और कमजोर आर्थिक वृद्धि दर शामिल हैं। रुपया संभालने और विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए ब्याज दर बढ़ाने के बजाय आरबीआई को शायद अन्य विकल्पों पर विचार करने की जरूरत है। विदेशी मुद्रा बाजार में केंद्रीय बैंक हा हस्तक्षेप कारगर नहीं रहने वाला है। आक्रामक खुले बाजार संचालन के माध्यम से ब्याज दर कम करने और खरीद-बिक्री स्वेप के माध्यम से नकदी उपलब्ध कराने से घरेलू निवेशकों के लिए ऋदा दरें अधिक आकर्षक नहीं रह जाती हैं जिससे वे शेयर बाजार की तरफ रुख करने लगते हैं।

विदेशी निवेशक अन्य कारणों से बाजार से दूर भाग रहे हैं। डॉलर बेचने और ब्याज दरें बढ़ाने के अलावा अन्य विकल्पों पर विचार करने का समय आ गया है। इनमें से एक विकल्प प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) की जमा राशि बढ़ाना हो सकता है। आरबीआई ने वर्ष 2०13 में इसी तरीके से 26 अरब डॉलर जुटाए थे जिसमें एक रियायती स्वेप विंडो विकल्प की पेशकश की गई थी। इस विकल्प के माध्यम से बैंक जुटाई गई विदेशी मुद्रा जमा कर सकते थे और बदले में रुपये के समतुल्य राशि हासिल कर सकते थे, साथ ही विनिमय दर से जुड़े जोखिमों से कम एवं निश्चित दर पर पूरी तरह बच सकते थे। आरबीआई कंपनियों के लिए भी बैंकों के माध्यम से विदेशी पूंजी जुटाने हेतु इसी तरह का फॉर्मूला तैयार कर सकता है। बेशक, पूंजी की एक लागत होती है मगर फिलहाल इसे आजमाना उचित है क्योंकि मौजूदा हालात देश में विदेशी रकम की आपद के लिए माकूल नहीं लग रहे हैं। साल की दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति बढ़ेगी और आर्थिक गति भी धीमी होगी। ऐसे में फिलहाल ब्याज दरों में बढ़ोतरी टाली जा सकती है।

-धनंजय राजौरा

जनसुनवाई में आमजन को मिला प्रशासन का भरोसा, कलेक्टर ने सुनीं समस्याएं

फिर ठप्प हुई नगर की जलापूर्ति व्यवस्था, केबल में हुआ फाल्ट

8 से 10 घंटे देरी से शुरू हुआ जलप्रदाय, परेशान हुए नगरवासी

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिला मुख्यालय पर मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर ऋगुराज सिंह ने आमजन की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रकरणों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर संजीव जैन, संयुक्त कलेक्टर अंशु जावला सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

जनसुनवाई के दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया। कलेक्टर ने प्रत्येक आवेदन पर संवेदनशीलता के साथ सुनवाई करते हुए संबंधित



अधिकारियों को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वृद्धा पेंशन शुरू कराने की मांग- ग्राम टिगरिया सांचा निवासी रेशमबाई ने वृद्धा पेंशन शुरू कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

कलेक्टर ने संबंधित विभाग को मामले की जांच कर पात्रानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

गौचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग- ग्राम अकालिया निवासी कमल किशोर विश्वकर्मा ने गौचर भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए आवेदन दिया। इस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को जांच कर

आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मकान मुआवजा दिलाने का आवेदन- कालापाठ निवासी ब्रदी पिता गजु ने मकान का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने प्रकरण की जांच

कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

खेत के पानी की निकासी का मामला- आंवलियापिपल्या निवासी संदीप यादव ने खेत के पानी की निकासी बाधित होने की समस्या बताते हुए पाली हटवाने की मांग की। कलेक्टर ने संबंधित विभाग को मौके की जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

अन्य मामलों पर भी सुनवाई- जनसुनवाई में प्रधानमंत्री आवास योजना, जमीन सीमांकन, बिजली बिल संशोधन, बीपीएल सूची में नाम जोड़ने, नामांतरण, बंटवारा, रास्तों से अतिक्रमण हटाने, नालियों की सफाई सहित विभिन्न विषयों से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने सभी प्रकरणों पर संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर जांच कर शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। नगर के बेछा रोड स्थित सांपखेड़ा गांव में इंटेकवेल पंप की विद्युत केबल में सोमवार रात अचानक फाल्ट आ गया। तकनीकी खराबी के कारण मंगलवार को शहर की जलप्रदाय व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। विद्युत आपूर्ति बाधित होने से इंटेकवेल से पानी की सप्लाई नहीं हो सकी, जिससे पूरे नगर में पेयजल संकट खड़ा हो गया। नगर में करीब 8 से 10 घंटे की देरी से जलप्रदाय किया जा सका।



नगर में वर्तमान में एक दिन छोड़कर जल वितरण किया जा रहा है। ऐसे में निर्धारित दिन पर पानी की

आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से जल्द से जल्द समस्या का समाधान कर पानी की सप्लाई बहाल करने की मांग की।

इंदौर से आई विशेषज्ञों की टीम

आपूर्ति न होने से कई क्षेत्रों के नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अनेक मोहल्लों में लोगों को पेयजल के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी। नागरिकों का कहना है कि पहले से ही सीमित अंतराल में जलापूर्ति होने के कारण सप्लाई बाधित होने पर स्थिति और गंभीर हो जाती है। लोगों ने बताया कि नियमित जलापूर्ति न होने से

नगर पालिका के जलकर सभापति प्रेम यादव ने बताया कि इंटेकवेल की विद्युत केबल में फॉल्ट आने के कारण जलप्रदाय प्रभावित हुआ है। फॉल्ट को सुधारने के लिए इंदौर से विशेषज्ञ टीम और आवश्यक सामग्री भेजी गई है। कर्मचारी लगातार सुधार कार्य किया गया जिसके बाद जल वितरण किया जा सका।

समयावधि पत्रों का समय सीमा में हो निराकरण— आयुक्त



देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। समयावधि पत्रों एवं सीएम हेल्प लाइन की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए विभाग के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश आयुक्त दलीप कुमार ने दिए। विद्युत खपत एवं विद्युत देयकों के विषय एवं पॉवर फेक्टर की जानकारी संबंधित अधिकारी से ली। पीएम स्वनिधि में हितग्राहियों को दिये जाने वाले ऋणों में प्रगति में कम पाये जाने पर आगामी 15 दिवस में सुधार एवं लक्ष्य पूर्ति के लिए कहा। वहीं अनुग्रह सहायता राशि एवं ई-केवाईसी को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए। स्वच्छता निरीक्षकों को उनके झोले क्षेत्र में मैरीज गार्डनों का निरीक्षण कर रिपोर्ट दिए जाने हेतु कहा। आयुक्त ने अमृत हरित अभियान की जानकारी लेते हुए निर्धारित स्थानों पर पौधे लगाने का प्लान 7 दिवस में तैयार किए जाने हेतु कहा। वर्षाकाल में जल जमाव की स्थिती से निपटने एवं पानी की निकासी की व्यवस्था पर कार्य करने के निर्देश दिए। लक्ष्य पूर्ति एवं अधिक से अधिक रूप वॉटर हार्वैस्टिंग सिस्टम लगाये जाने के साथ ही गार्डनों में भी शॉक पीट लगाकर रिपोर्ट देने हेतु कहा। वर्षा पूर्व सिवरेज के चेम्बरो की सफाई कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। सभी वार्ड उपयंत्री अपने अपने वार्डों में जीर्णोद्धार भवन जो वर्षाकाल में गिरने की स्थिती में हैं उन्हें चिह्नीत कर भवनों के स्वामियों से समन्वय कर तोड़ने की कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु कहा। कम्पाउंडिंग कार्य में प्रगति नहीं होने पर आयुक्त ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कार्य में तेजी लाने के साथ लक्ष्य पूर्ति करने हेतु कहा। आयुक्त ने समयावधि पत्र एवं सीएम हेल्प लाईन की शिकायतों के समय पर निराकरण के निर्देश दिए।

ई- विकास पोर्टल के माध्यम से किसानों को मिलेगा पर्याप्त उर्वरक

सीहोर/दैनिक मालवा हेराल्ड। ई-विकास पोर्टल के माध्यम से किसानों को उनके रकबे के अनुसार फसल जैसे मक्का धान, सोयाबीन आदि चयन करने पर एक ही बार में संपूर्ण उर्वरक मिल सकेगा। ई-टोकन प्रणाली में कृषक अपने मोबाइल से आसानी से टोकन जारी कर उर्वरक बुक कर सकते हैं अथवा एमपी ऑनलाइन केन्द्रों पर 15 रुपये का शुल्क देकर भी टोकन जारी करा सकते हैं। सिकमी (ठेकेदार/बटाईदार) किसान जो भूमि स्वामी नहीं है वे अपने भू-स्वामी की अनुमति से एग्री स्ट्रेक पोर्टल के माध्यम से अधिकृत प्रतिनिधि किसान बनकर ई-टोकन बुक कर सकते हैं।

वन पट्टाधारी किसान एसडीएम के सत्यापन के उपरांत ई-विकास पोर्टल के माध्यम से उर्वरक बुक कर सकते हैं। मृत शारीरिक रूप से अश्वय एवं वृद्ध किसानों हेतु भी ई-विकास प्रणाली पर उर्वरक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। संयुक्त खाताधारी कृषकों जिनमें से एक या अन्य सदस्य किसी अन्य शहर में या देश के बाहर रहते हैं जिस कारण उनका आधार

ओ.डी.सी प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता ऐसे किसानों अथवा संयुक्त खाता धारकों में से किसी एक किसान को नामांकित करने के लिए ई-विकास पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध है।

ऐसे करें ई टोकन जारी- पंजीयन के लिए किसानों को अपना आधार नम्बर एग्रीस्ट्रेक पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। फार्मर आईडी पर रकबा, खसरा एवं फसल की जानकारी अद्यतन होना आवश्यक है। आधार से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओटीपी के माध्यम से पंजीयन की प्रक्रिया करनी होती है इसलिए मोबाइल नम्बर का आधार से लिंक होना आवश्यक है। ई-टोकन जारी करने के लिए ई-विकास पोर्टल के डेशबोर्ड पर ऑप्शन पर क्लिक करने के उपरांत आधार नम्बर प्रविष्ट करना होगा। किसान के आधार से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ.टी.पी. डालने पर उस किसान की भूमि और पट्टे की जानकारी आयेगी। कृषक को भूमि के लिए फसल तय करना होगा जिससे उर्वरक की मात्रा स्वतः पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। यूरिया के साथ डीएपी अथवा एसएसपी या एनपीके का विकल्प चुनना

होगा। चयनित फसल एवं उपलब्ध रकबे के अनुसार आवश्यक उर्वरक का प्रकार चुनने के उपरांत वितरण केन्द्र डबल लॉक केन्द्र एमपी एग्री स्ट्रेक पोर्टल पर सुविधा निजी विक्रेताओं पर उपलब्ध स्टॉक प्रदर्शित होगा जिसके चयन के उपरांत ई-टोकन जारी हो जायेगी।

उर्वरक का उठाव- जारी टोकन के साथ किसान को 02 दिन के भीतर चयनित वितरण केन्द्र से ख़ाद प्राप्त करना होगा। यदि किसान समय सीमा में ख़ाद नहीं लेता है तो टोकन स्वतः निरस्त हो जायेगा। ख़ाद के लिए लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होगी।

आवश्यक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जिन किसानों के फार्मर आई.डी. नही बने है उन्हें जल्द से जल्द अपनी फार्मर आई.डी बनवा लेनी चाहिए।

विशेष परिस्थिति में फार्मर आईडी न होने पर एसडीएम के अफ़्वल से टोकन बुक करने की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। यदि किसान को अतिरिक्त उर्वरक की आवश्यकता है तो वह पोर्टल पर औचित्य दर्ज कर अतिरिक्त उर्वरक प्राप्त कर सकता है।

भीषण गर्मी में भी झेला जलसंकट, अब भी नहीं मिल रहा पर्याप्त पानी

ग्रामीणों ने तहसीलदार व सीईओ को ज्ञापन सौंपा की नियमित जलापूर्ति की मांग

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले के मो.बड़ोदिया में भीषण गर्मी झेल रहे मोहन बड़ोदिया के रहवासियों के सब्र का बांध टूट चुका है। क्योंकि पिछले 6 माह से वे जलसंकट झेल रहे हैं। कई लोगों का पूरा दिन पानी की व्यवस्था में बीत जाता है। इसे लेकर मंगलवार को ग्रामीणों ने मंगलवार को एक ज्ञापन तहसीलदार व सीईओ को सौंपा। जिसमें समस्या समाधान की मांग की। वहीं समस्या हल न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

मंगलवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसील और जनपद कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या बताई। उन्होंने नायब तहसीलदार मुकेश गुप्ता और जनपद पंचायत सीईओ अमृतराज सिसोदिया को शिकायत आवेदन सौंपा। जिसमें बताया कि कुछ माह पहले शाजापुर कलेक्टर ने भी मोहन बड़ोदिया का दौरा किया था। उस समय



ग्रामीणों ने कलेक्टर को समस्या से अवगत कराया था। कलेक्टर ने अनियमितता पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने मांग की है कि कंपनी द्वारा नल जल योजना के तहत डाली गई पाइपलाइन की व्यवस्था सुधारी जाए और मोहन बड़ोदिया के सभी

नगरवासियों को प्रत्येक घर तक पानी मिले। क्योंकि योजना के तहत जिन घरों में नल कनेक्शन दिए गए हैं वहां ठीक से पानी नहीं पहुंचता जिससे यह योजना किसी काम की नहीं है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि मो. बड़ोदिया में जब नल जल सर्वे हुआ था तब कहा गया था की नलो में पानी तीसरी मॉजल तक बिना मोटर के चढ़ सकेगा, लेकिन प्रेशर तो दूर पानी ही उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि बल्डी पर बनाई गई बड़ी टंकी से गांव को जोड़ा जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि योजना के तहत कंपनी द्वारा जो पाइप डाले गए हैं वह भी काफी कमजोर किस के हैं जो

आए दिन क्षतिग्रस्त होते रहते हैं। जिससे काफी मात्रा में पानी व्यर्थ बह जाता है। वहीं जो नल कनेक्शन किए गए हैं उनमें से 50 कनेक्शन तो ऐसे है जो सीधे में लाइन से जोड़ दिए गए हैं। जिससे भी प्रतिदिन पानी व्यर्थ बहता रहता है जिसे रोका जाना जरूरी है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से प्रतिदिन जलप्रदाय किए जाने की मांग की है ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके।

चक्काजाम की दी चेतावनी- समस्या लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि आठ दिन के भीतर उनकी पानी की समस्या का समाधान नहीं होता है तो वे नौवें दिन आगर-सारांगपुर रोड पर चक्का जाम करेंगे। इसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन और जल विभाग की होगी। मामले में नायब तहसीलदार मुकेश गुप्ता ने ग्रामीणों को बताया कि उनकी समस्या के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।

मोहन बड़ोदिया जनपद पंचायत सीईओ अमृतराज सिसोदिया ने जल विभाग के अधिकारी से फोन पर बात की और एक-दो दिन में समस्या का निराकरण करने को कहा। उन्होंने संबंधित ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर करने की बात भी कही।

6 माह पहले दिए कनेक्शन, अब तक शुरू नहीं की सप्लाई- ग्रामीणों ने सौंपे गए आवेदन में बताया कि मोहन बड़ोदिया की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अस्पताल कालोनी में भी योजना के तहत 6 माह पहले नल कनेक्शन दिए गए थे, लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं दिए गए और मुख्य पाइप लाइन से पानी की आपूर्ति नहीं जोड़ी गई है। जिससे यहां रहने वाले लोग भी जलसंकट का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इस अधूरे कार्य को भी जल्द पूरा करने की मांग की है ताकि अस्पताल कालोनी के निवासियों की भी समस्या हल हो सके।

युवक कांग्रेस ने वाहन चालकों को खिलाई मेलोंडी

पेट्रोल पंप पर मूल्य डीजल-पेट्रोल मूल्य वृद्धि का किया अनोखा विरोध

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। युवक कांग्रेस द्वारा पेट्रोल-डीजल के मूल्य में हो रही वृद्धि को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पहुंचकर पहले तो जमकर नारेबाजी की। इसके बाद जो भी वाहन चालक पेट्रोल भरवाने आए उन्हें मेलोंडी चॉकलेट बांटकर कहा ‘‘मेलोंडी खाओ, पेट्रोल भरवाओ’’। इस विरोध के तरीके से वाहन चालक भी मुस्कुराते नजर आए।

दरअसल पेट्रोल-डीजल के भाव पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। लोगों का कहना है कि हम घर चलाएं या गाड़ी। इसी को लेकर मंगलवार को युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने इस मूल्य वृद्धि के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता वीरेंद्रसिंह गोहिल ने कहा कि आज प्रदेश और केंद्र में बैठे लोग आम लोगों की जेब



पर सीधे डाका डाल रहे हैं। वे लोगों से तो खर्चों में कटौती करने, सोना न खरीदने की अपील करते हैं और खुद वाहनों के काफिलों में घूम-घूमकर जनता के पैसों पर पेश कर रहे हैं। लगातार मूल्य वृद्धि की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार कर्ज लिए जा रही है जिसका बोझ जनता के कंधे पर डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब जनता इनकी कारगुजारियों से तंग आ चुकी है जिसका गुस्सा भी अब लोगों में नजर आने लगा है और जनता इन्हें जवाब देने को तैयार है। इस अवसर पर किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष कैलाश मटोलिया, दीपक

निगम, मांगीलाल नायक, धर्मेन्द्र प्रजापति, राम शर्मा, रियान खान, योगेश वर्मा, सौरभ गवली, कैफ खान, लखन मंडावर, मोहित माहेश्वरी, इरशाद पिपिलिया, गोविंद वर्मा, सरलेश चतुर्वेदी, शैलेंद्र अहिरवार, दीपक सलोकिया, इश्वर सिंह, नावेद खान, अनवर खान, कबीर कुरैशी, सिद्धिक खान सहित बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे।

मेलोंडी खाओ, पेट्रोल भरवाओ- युवक कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष इरशाद नागोरी के नेतृत्व में मंगलवार को कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पेट्रोल पंप पहुंचे और वहां पेट्रोल लेने आए लोगों को मेलोंडी चॉकलेट का वितरण किया और कहा कि मेलोंडी खाओ पेट्रोल भरवाओ। इस विरोध प्रदर्शन की लोगों ने भी सराहना की और मूल्य वृद्धि को लेकर अपनी बात कही।

अविवादित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन प्रकरणों का तय समय सीमा में निराकरण करें- कलेक्टर श्री सिंह

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री ऋगुराज सिंह की अध्यक्षता में समय-सीमा संबंधी लॉबित पत्रों के निराकरण की प्रगति तथा अंतरविभागिय समन्वय से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री दलीप कुमार, अपर कलेक्टर श्री शोभाराम सोलंकी, अपर कलेक्टर श्री संजीव जैन, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती प्रिया चंद्रावत, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती विशाखा देशमुख, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती अंशु जावला सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारिगण उपस्थित थे। समय-सीमा संबंधी बैठक में विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने अविवादित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन प्रकरणों की समीक्षा कर निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश नहीं की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारी तय समय सीमा में अविवर्धित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन प्रकरणों का निराकरण करें। कलेक्टर श्री सिंह



ने भूमि आवंटन प्रकरणों की समीक्षा कर भूमि आवंटन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने पट्टा नवीनीकरण एवं फॉर्मर रजिस्ट्री कार्य की समीक्षा कर शत-प्रतिशत कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर श्री ऋगुराज सिंह ने जल गंगा संवर्धन अभियान की प्रगति की विस्तृत समीक्षा कर अभियान के तहत जल स्रोतों के पुनरुद्धार सहित अभियान के तहत किए जा रहे अन्य कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत चिन्हित किए गए कुएँ, बावड़ी, तालाब और नदियों के संरक्षण कार्य को समय सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अनुभाग अंतर्गत तालाबों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। कलेक्टर श्री सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की विस्तृत समीक्षा कर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह जिले में योजना के तहत स्वीकृत आवासों, जारी किरतों और निर्माण की वर्तमान स्थिति की बिंदुवार समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि जिले को प्रधानमंत्री आवास योजना में 7203 का लक्ष्य दिया है, जिसमें जिले में 6746 आवास स्वीकृत हो गए हैं। 3958 आवासों में प्रथम किस्त जारी हो गई है तथा 06 आवास पूर्ण हो गये हैं। कलेक्टर श्री सिंह ने समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन आवासों की स्वीकृति शेष है, उन्हें तुरंत पूरा किया जाए।

कलेक्टर श्री सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की विस्तृत समीक्षा कर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह जिले में योजना के तहत स्वीकृत आवासों, जारी किरतों और निर्माण की वर्तमान स्थिति की बिंदुवार समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि जिले को प्रधानमंत्री आवास योजना में 7203 का लक्ष्य दिया है, जिसमें जिले में 6746 आवास स्वीकृत हो गए हैं। 3958 आवासों में प्रथम किस्त जारी हो गई है तथा 06 आवास पूर्ण हो गये हैं। कलेक्टर श्री सिंह ने समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन आवासों की स्वीकृति शेष है, उन्हें तुरंत पूरा किया जाए।

कलेक्टर श्री सिंह ने जल जीवन मिशन अंतर्गत एकल नल-जल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर पूर्ण योजनाओं को शीघ्र हैंड ओवर करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्ण हो चुकी नल जल योजनाओं को अलग-अलग समय पर हैंडओवर नहीं कर के माह में एक दिन सुनिश्चित कर नल जल योजनाओं को हैंड ओवर करें। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जल अर्पण दिवस का आयोजन कर योजना को हैंड ओवर करें।

कलेक्टर श्री सिंह ने जिले की सभी जनपद पंचायतों एवं नगर परिषदों में चल रहे ई-केवाईसी कार्य की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने एक-एक कर सभी नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में ई-केवाईसी की वर्तमान स्थिति को देखा। उन्होंने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अभियान चलाकर शत प्रतिशत ई-केवाईसी का कार्य शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

थाना बड़ावदा बना ISO (आईएसओ) प्रमाणित थाना

इकाई उज्जैन की ट्रेप कार्यवाही

प्रवीण व्यास/दैनिक मालवा/हेराल्ड। आधुनिक प्रबंधन, तकनीकी नवाचार एवं जनकेंद्रित पुलिसिंग के उत्कृष्ट मॉडल के रूप में मिली मान्यता रिकॉर्ड प्रबंधन, चक्र आधारित ट्रेकिंग सिस्टम, महिला हेल्प डेस्क एवं नागरिक सुविधाओं में नवाचारों को मिला राष्ट्रीय स्तर का प्रमाणन पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री अमित कुमार के निर्देशन में जिले के सभी थानों एवं पुलिस कार्यालयों के मानकीकरण एवं सुव्यवस्थित करने के प्रयासों के फलस्वरूप जिले के एक और थाना बड़ावदा को आई एस ओ प्रमाण पत्र मिला।

दिनांक 02.06.26 को पुलिस उप महानिरीक्षक रतलाम रेंज श्री निमिष अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री अमित कुमार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार की उपस्थिति में थाना प्रभारी बड़ावदा श्री वैभव प्रिय (प्रशिक्षु आई पी एस) को दृष्टुष्ट प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी बड़ावदा श्री वैभव प्रिय (प्रशिक्षु आई पी एस)एवं थाना बड़ावदा टीम को आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु किए गए प्रयासों एवं मेहनत की सराहना की।

इस अवसर पर प्रशिक्षु भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी एवं थाना प्रभारी बड़ावदा श्री वैभव प्रिय ने कहा कि यह ISO



Certification केवल एक प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि पुलिस विभाग की पारदर्शिता, जवाबदेही एवं उत्कृष्ट जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि पुलिस थाना केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने का केंद्र नहीं, बल्कि आमजन के विश्वास का भी केंद्र होता है। इसी विश्वास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से थाना बड़ावदा में विभिन्न सुधारात्मक एवं नवाचारात्मक पहलें की गई हैं।

रिकॉर्ड प्रबंधन में व्यापक सुधार- थाना बड़ावदा में वर्षों से संधारित अभिलेखों का वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण एवं व्यवस्थित प्रबंधन किया गया। मध्यप्रदेश पुलिस

विनियमों एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप अनुपयोगी अभिलेखों का विधिवत रिकॉर्ड डिस्ट्रक्शन कर रिकॉर्ड रूम को अधिक सुव्यवस्थित एवं उपयोगी बनाया गया, जिससे आवश्यक अभिलेखों तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित हुई है।

QR Code आधारित मालखाना प्रबंधन प्रणाली- जन्म संपत्तियों के संरक्षण एवं पारदर्शी प्रबंधन हेतु मालखाने का पूर्ण पुनर्गठन किया गया है। प्रत्येक जन्म संपत्ति को चक्र दृश्यसदृश से टैग कर डिजिटल ट्रेकिंग प्रणाली विकसित की गई है, जिससे वस्तु की स्थिति, स्थान एवं मूवमेंट की जानकारी त्वरित रूप से उपलब्ध हो सकेगी। यह पहल मालखाना प्रबंधन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

QR आधारित Vehicle Tracking System- न्यायालयीन आदेशों के अंतर्गत थाना परिसर में रखे गए वाहनों के बेहतर प्रबंधन हेतु QR Code आधारित Vehicle Tracking System प्रारंभ किया गया है। इस प्रणाली से प्रत्येक वाहन का डिजिटल रिकॉर्ड एवं अद्यतन जानकारी सरलता से प्राप्त की जा सकती है, जिससे वाहन प्रबंधन अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी हुआ है।

नागरिक सुविधाओं का विस्तार- थाना परिसर में आमजन की सुविधा हेतु शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए Water Cooler स्थापित किया गया है। साथ ही नागरिकों एवं कर्मचारियों के लिए सुव्यवस्थित Vehicle Parking विकसित की गई है, जिससे थाना परिसर अधिक व्यवस्थित एवं नागरिक अनुकूल बन सका है।

उर्जा महिला हेल्प डेस्क का पुनरोद्धार- महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए उर्जा महिला हेल्प डेस्क का व्यापक रूप से पुनरोद्धार किया गया है। हेल्प डेस्क को अधिक संवेदनशील, सुविधाजनक एवं नागरिक हितैषी स्वरूप प्रदान किया गया है, जिससे महिला पीड़िताओं को सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण में सहायता प्राप्त हो सके।

Citizen Feedback System की शुरुआत- जनसंपर्क एवं पुलिस सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के उद्देश्य से चक्र दृश्यसदृश आधारित Citizen Feedback System प्रारंभ किया गया है। अब कोई भी नागरिक अपने मोबाइल फोन के माध्यम से तत्काल फीडबैक दे सकता है। प्राप्त सुझाव एवं प्रतिक्रियाएं पुलिस सेवाओं के सतत मूल्यांकन एवं सुधार में सहायक सिद्ध होंगी। खेल एवं सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा- पुलिस बल के शारीरिक स्वास्थ्य एवं सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित

करने हेतु थाना परिसर में आधुनिक Volleyball Court का निर्माण कराया गया है। इस सुविधा का लाभ पुलिस कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय युवा एवं नागरिक भी प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल पुलिस एवं समाज के मध्य संवाद एवं विश्वास को और अधिक मजबूत करने में सहायक होगी।

ISO Certification बना उत्कृष्ट पुलिसिंग का प्रतीक- प्रशिक्षु IPS श्री वैभव प्रिय ने कहा कि ISO Certification थाना बड़ावदा द्वारा किए गए सभी सुधारात्मक प्रयासों की औपचारिक मान्यता है। यह उपलब्धि भविष्य में और अधिक उत्कृष्टता, पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार एवं जनकेंद्रित पुलिसिंग की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करेगी।

उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय थाना स्टाफ, वरिष्ठ अधिकारियों एवं आमजन के सहयोग को देते हुए कहा कि पुलिस एवं जनता के संयुक्त प्रयासों से ही आधुनिक एवं विश्वास आधारित पुलिसिंग का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

इस दौरान सीएसपी जावरा श्री युवराज सिंह चौहान, एसडीओपी जावरा श्री सदीप मालवीय, रक्षित निरीक्षक श्री मोहन भारीवत, थाना बड़ावदा स्टाफ समस्त थाना एवं चौकी के प्रभारी तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं रक्षित लाइन का स्टाफ उपस्थित रहा।



उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। महानिदेशक, लोकायुक्त श्री योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने के निर्देश पर उप पुलिस महानिरीक्षक श्री मनोज सिंह जी के प्रभावी मार्गदर्शन में लोकायुक्त सभाग उज्जैन के द्वारा सफल ट्रेप कार्यवाही, ट्रेप दिनांक 02.06.2026, नाम आवेदक -ललित मीणा, वनरक्षक, गांधी

सागर परिक्षेत्र मंदसौर, आरोपी - कृष्ण प्रताप सिंह राठौर, स्थापना शाखा प्रभारी, सामान्य वनमंडल मंदसौर. रिश्तत राशि- 3,000/-रूपए, कार्य का विवरण - आवेदक द्वारा स्वयं के ईलाज हेतु 43 दिवस अर्जित अवकाश हेतु विभाग के टूब्रक्स पोटल के माध्यम से दिनांक 27.05.2026 को ऑनलाइन किए गए आवेदन को आरोपी कृष्ण प्रताप सिंह राठौर, जिनकी आई.डी. में उक्त आवेदन लंबित था, को आगे अग्रपिठित करने एवं स्वीकृत करवा देने के नाम पर 3,000/-रूपए लेते ट्रेप किया गया । आरोपी के विरुद्ध धारा-7 ध्र0नि0संशे0अधि0 2018 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया । टीम द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

ट्रेप दल -डीएसपी श्री दिनेशचंद्र पटेल, निरीक्षक हीना डावर, प्र. आर. हितेश ललावत, आर. उमेश जाटव, आर. श्याम शर्मा, आर. मो. इसरार, लोकायुक्त संगठन द्वारा लगातार भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । आमजन से अपील है कि यदि कोई लोकसेवक अधिकारी, कर्मचारी किसी शासकीय कार्य को करने हेतु रिश्तत की मांग करता है, तो लोकायुक्त उज्जैन को मोबाईल नंबर 9425103975 पर अथवा शासकीय दूरभाष 0734-2512756 पर सम्पर्क कर सकता है ।

कलेक्टर ने रामा तहसील कार्यालय में तड़वी एवं कोटवारों की बैठक ली

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने रामा तहसील कार्यालय में तड़वी एवं कोटवारों की बैठक लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी भूमिका एवं दायित्वों पर चर्चा की। बैठक में कलेक्टर ने तड़वी एवं कोटवारों को प्रशासन और ग्रामीण समुदाय के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए विभिन्न विषयों पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में सर्पदंश, दुर्घटनाओं एवं अन्य आपातकालीन घटनाओं की सूचना तत्काल प्रशासन तक पहुंचाने तथा जनजागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने तड़वी एवं कोटवारों से उनके क्षेत्रों की स्थिति एवं समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण समुदाय स्वयं प्रेरित होकर सामाजिक सुधार के लिए निर्णय ले तथा प्रशासन ऐसे सकारात्मक प्रयासों में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। बैठक में गांवों में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने, किसी भी संदिग्ध अथवा महत्वपूर्ण गतिविधि की जानकारी तत्काल प्रशासन को देने तथा अपराधी समन्वय एवं संवाद के माध्यम से छोटे-मोटे विवादों को सुलझाने के प्रयास करने पर बल दिया गया। कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सामाजिक मुद्दों पर जनजागरूकता करने तथा शासन की योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने तड़वी एवं कोटवारों से अपेक्षा व्यक्त की कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए गांवों के विकास, सामाजिक समरसता एवं जनहित के कार्यों में सक्रिय योगदान दें।

उज्जैन पुलिस रेडियो शाखा में पदस्थ सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस विभाग के दो अधिकारियों को आयोजित गरिमामय समारोह में सम्मानपूर्वक विदाई दी गई



उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। पुलिस विभाग के लिए एक भावुक और विदाई का क्षण रहा। पुलिस विभाग में एक लंबी और समर्पित सेवा के बाद सेवानिवृत्त होना किसी भी अधिकारी के जीवन का एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है। पुलिस अधीक्षक रेडियो जिला उज्जैन में आज अपनी सेवाएं पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों को शाल श्रीफल एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यवाहक निरीक्षक अनिल कुमार सराफ को 43 वर्ष एवं कार्यवाहक उप निरीक्षक राकेश सिंह भदौरिया ने

41 वर्ष की पुलिस विभाग को अपनी सेवाएं दी। पुलिस विभाग में रेडियो शाखा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जो कानून व्यवस्था और संचार व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। इन दोनों अधिकारियों ने अपने लंबे सेवाकाल में उज्जैन पुलिस और जनता की सुरक्षा में जो योगदान दिया है, वह सराहनीय है।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रेडियो उज्जैन द्वारा सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पुष्पमाला पहनाकर, शॉल एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मान किया गया। विदाई समारोह के दौरान उपस्थित अधिकारियों-कर्मचारियों ने भी सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ अपने अनुभव साझा किए तथा उनके योगदान की सराहना करते हुए उन्हें भावभीनी विदाई दी। उज्जैन पुलिस परिवार की ओर से सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके आगामी जीवन अच्छे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगलकामनाएं बधाई दीं।

तीन साल बाद भी कार्रवाई नहीं, अब जीतू पटवारी ने उठाए सवाल; बोले- भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जनपद पंचायत जावद के अध्यक्ष गोपाल चारण के रिश्तत लेते पकड़े जाने के मामले में लगभग तीन साल बीत जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन को घेरा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इस मामले में सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

नीमच में मीडिया से चर्चा के दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि शासन और जिला प्रशासन को इस मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों

में कार्रवाई होना जरूरी है। यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो भविष्य में कांग्रेस सरकार बनने पर भ्रष्टाचार करने वालों के साथ-साथ उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पटवारी ने कहा, जनपद अध्यक्ष भ्रष्टाचार के मामले में शासन को जागना चाहिए, डीएम को ध्यान देना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ काम होना चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो सरकार आने पर भ्रष्टाचार करने वालों को सजा दी जाएगी और जो उन्हें बचा रहे हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा।

इससे पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री

दिग्विजय सिंह ने 30 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पर पोस्ट कर नीमच कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से कई सवाल पूछे थे। उन्होंने पूछा था कि रिश्तत लेते रहे हाथों पकड़े जाने के बावजूद गोपाल चारण की गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई क्यों नहीं हुई और उन्हें पद से क्यों नहीं हटाय़ा गया। साथ ही पंचायतों में भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी पाए गए सरपंचों और सचिवों के विरुद्ध पंचायत अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने जवाब नहीं मिलने की स्थिति में जनसुनवाई में पहुंचने की बात भी कही थी।

गौरतलब है कि 27 मार्च 2023 को लोकायुक्त पुलिस ने जनपद पंचायत जावद के अध्यक्ष गोपाल चारण को 50 हजार रुपए की रिश्तत लेते हुए गिरफ्तार किया था। आरोप था कि ग्राम पंचायत खोर के सरपंच बलराम जाट से ग्राम खेड़ा राठौर में सामुदायिक भवन सह ई-कक्ष निर्माण के लिए स्वीकृत पांच लाख रुपए की योजना को मंजूरी देने के एवज में रिश्तत मांगी गई थी। लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद मामला सुर्खियों में आया था, लेकिन तीन साल बाद भी किसी बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के अभाव में अब यह मुद्दा फिर से राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है।

मलेरिया पर प्रहार, जागरूकता से उपचार, जून मलेरिया निरोधक माह के तहत कलेक्ट्रेट में अंतर विभागीय कार्यशाला संपन्न

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। प्रतिवर्षानुसार माह जून को मलेरिया निरोधक माह के रूप में मनाया जा रहा है। मच्छर जनित बीमारियों यथा मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया इत्यादि के संबंध में आमजन में जागरूकता लाने हेतु जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

अंतर विभागीय कार्यशाला संपन्न- इसी क्रम में मंगलवार को टी.एल. बैठक के पश्चात कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में मलेरिया निरोधक माह जून 2026 के अंतर्गत विभिन्न विभागों से समन्वय हेतु अंतर विभागीय

कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, नीमच में किया गया। कार्यशाला में समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर के निर्देशन-कलेक्टर ने समस्त विभागों को निर्देशित किया कि मानसून के दौरान मच्छरों की उत्पत्ति के स्रोत बढू जाते हैं, जिससे मच्छर जनित बीमारियां फैलने लगती हैं। मच्छर के उत्पत्ति स्रोतों को नष्ट कर ही इन बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। उन्होंने सभी विभागों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में मच्छरजन्य परिस्थितियों को समाप्त कर

बीमारियों के नियंत्रण में सक्रिय सहयोग करने के निर्देश दिए। जिला मलेरिया अधिकारी की अपील- जिला मलेरिया अधिकारी श्री अल्पेश कुमार बारिया ने समस्त विभागों से अपील की कि वे अपने कार्यालय परिसर, आवासीय कॉलोनियों एवं कार्यस्थलों पर जल-जमाव न होने दें। कुत्तर, गमले, टायर, नारियल के खोल आदि में एकत्र पानी को नियमित रूप से खाली करें। मच्छरजन्य परिस्थितियों को नष्ट करने में प्रशासन का सहयोग करें, जिससे जिले को मलेरिया, डेंगू एवं चिकुनगुनिया मुक्त बनाया जा सके।

रामा ब्लॉक की स्वास्थ्य संस्थाओं का निरीक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. देवेन्द्र भायल एवं जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. जी.एस. चौहान द्वारा रामा विकासखंड अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं का निरीक्षण कर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण, परिवार नियोजन, आयुष्मान भारत योजना तथा संस्थागत व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामा के निरीक्षण के दौरान मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. शैलेश बाबेरिया की उपस्थिति में आयुष्मान कार्ड निर्माण कार्य की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने पात्र हिताग्रहियों के अधिक से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए। संस्था में साफ-सफाई एवं पेयजल व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि गत माह संस्था में 192 संस्थागत प्रसव एवं 36 आईयूसीडी लगाए गए। अधिकारियों ने परिवार नियोजन सेवाओं के विस्तार एवं पात्र दंपतियों को परिवार नियोजन साधनों के प्रति जागरूक करने पर विशेष बल दिया।

कलेक्टर ने रामा में सचिवों एवं पटवारियों की बैठक लेकर दिए महत्वपूर्ण निर्देश

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने रामा में सचिवों एवं पटवारियों की बैठक लेकर शासन की प्राथमिकताओं एवं जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है। लोगों से नियमित संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

कलेक्टर ने कहा कि सभी अपने मुख्यालय पर नियमित रूप से उपस्थित रहें तथा गांवों का सतत भ्रमण कर लोगों से सीधे संपर्क बनाए रखें। उन्होंने



जल संरक्षण एवं जल जीवन मिशन को जिले की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए बंद पड़ी नल-जल

संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा। सर्पदंश से होने वाली मृत्यु रोकने हेतु व्यापक

योजनाओं को शीघ्र चालू करने, पानी समितियों को सक्रिय करने तथा जल शुल्क संग्रहण एवं रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी शासकीय भवनों में वर्षा जल संचयन संरचनाएं विकसित करने तथा नरेंगा के माध्यम से जल

जनजागरण अभियान चलाने तथा अस्पतालों में एंटी-खेक वेनम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग को विद्यालयों एवं छात्रावासों में नियमित उपस्थिति, सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं की सतत निगरानी करने को कहा गया।

राजस्व विभाग को फार्मर आईडी का कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने, भूमि विवादों एवं अतिक्रमण प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित भ्रमण कर अभिलेखों का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि गरीबों की भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बैठक में वर्षाकाल के दौरान आपदा प्रबंधन की

तैयारियों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने जोखिम वाले स्थलों पर विशेष निगरानी रखने, जनहानि रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने तथा रहत प्रकरणों में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी ईमानदारी, पारदर्शिता एवं जनसेवा की भावना से कार्य करें तथा जिले के विकास और आमजन की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जितेंद्रसिंह चौहान, एसडीएम झाबुआ श्री महेश मंडलोई सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं सचिव, पटवारी उपस्थित रहे।

मालिक, प्रकाशक, मुद्रक विजय शर्मा द्वारा 44, बहादुरगंज, उज्जैन (म.प्र.) से प्रकाशित एवं भगवती ऑफसेट 44, बहादुरगंज, उज्जैन (म.प्र.) से मुद्रित। संपादक - विजय शर्मा, मो.नं. 942550-22499, फोन 0734-2553435 प्रधान संपादक - शुभम तापकार (सभी वाद विवाद का न्याय क्षेत्र उज्जैन रहेगा)

मध्यप्रदेश में पर्यटन का नया अध्याय



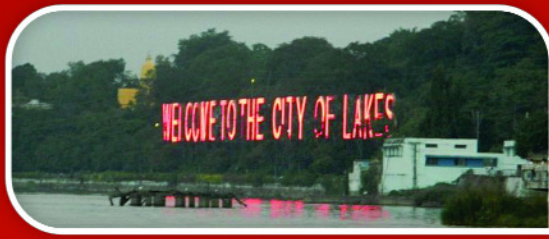
पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा

तेज, सुरक्षित और यादगार
यात्रा का अनूठा अनुभव



ओरछा

यहां भगवान राम
स्वयं इस नगर के
राजा के रूप में
विराजे हैं



भोपाल

झीलों की नगरी, मध्यप्रदेश
की राजधानी भोपाल
आधुनिक शहरी विकास और
सांस्कृतिक विरासत का केन्द्र

चंदेरी

प्राचीन किलों और हथकरघा
चंदेरी साड़ियों के लिए विश्व
प्रसिद्ध

मैहर

चित्रकूट पर्वत पर स्थित माँ
शारदा देवी मंदिर आस्था का
प्रमुख केंद्र

बांधवगढ़ नेशनल पार्क

सबसे अधिक संख्या में बाघों
की उपस्थिति। प्राकृतिक एवं
ऐतिहासिक पर्यटन का
अद्वितीय स्थल

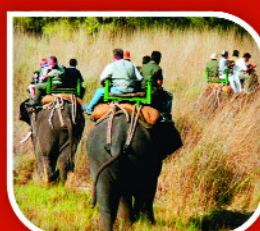
जबलपुर

भेड़ाघाट की संगमरमर की
घाटी, धुआंधार जलप्रपात
और प्राकृतिक सौंदर्य का
अद्वितीय अनुभव



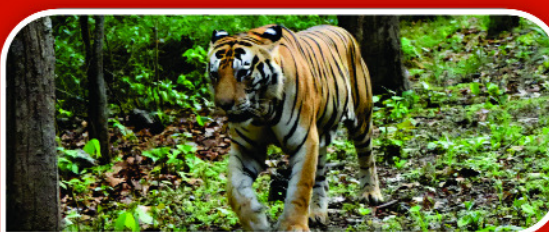
चित्रकूट

भगवान श्रीराम के वनवास से
जुड़ा, आध्यात्मिक महत्व का
अद्भुत स्थल



कान्हा नेशनल पार्क

सबसे प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व
समृद्ध वन्यजीव और
जैवविविधता का गढ़



इंदौर

मध्यप्रदेश की व्यापारिक राजधानी
होने के साथ-साथ स्वच्छता का
सिरमौर इंदौर अपने राजवाड़ा
सराफा और आधुनिक जीवन के
लिए प्रसिद्ध है



उज्जैन

भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग
और सिंहस्थ कुंभ जैसे विशाल
आध्यात्मिक आयोजन
के लिए विश्वविख्यात



ओंकारेश्वर

ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन और
अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य का
अनुभव



आध्यात्मिक सर्किट

इंदौर - उज्जैन - ओंकारेश्वर - इंदौर	₹30,000
इंदौर - उज्जैन - इंदौर	₹14,500
इंदौर - ओंकारेश्वर - इंदौर	₹18,000



हेरिटेज सर्किट

भोपाल से चंदेरी	₹5,500	चंदेरी से ओरछा	₹2,750
भोपाल से ओरछा	₹6,500	जॉय राइड	₹3,500
भोपाल - ओरछा - भोपाल	(विशेष पैकेज)		₹14,500



वाइल्डलाइफ एवं आस्था सर्किट

जबलपुर - मैहर	₹5,000	जबलपुर - बांधवगढ़	₹6,500
जबलपुर - चित्रकूट	₹7,500	जबलपुर - कान्हा	₹6,000
मैहर - चित्रकूट	₹5,000	बांधवगढ़ - कान्हा	₹7,000



एक संपूर्ण यात्रा पैकेज

- गंतव्य स्थल पर ठहरने की व्यवस्था से लेकर भोजन, स्थानीय टैक्सी तक हर सुविधा का पैकेज
- मंदिर दर्शन की पूर्व निर्धारित व्यवस्था, पर्यटन अनुभव को और खास बनाने के लिए गाइड
- हेलीपैड तक पिक-अप और ड्रॉप की सुविधा

बुकिंग

www.flyola.in
air.ircctc.co.in/flyola
www.transbharat.in